

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

भारत संवत् 2079 में प्रवेश कर रहा है, जो कई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की गति के साथ-साथ महामारी की तीसरी लहर का भी गवाह रहा है। हालाँकि, ये लाभ भू-राजनीतिक शत्रुता से उत्पन्न विघटनकारी प्रसार-प्रभाव के कारण जोखिम में हैं - जैसा कि मुद्रास्फीति प्रिंटों, सख्त वित्तीय स्थितियों और पोर्टफोलियो बहिर्वाह के साथ-साथ व्यापारिक आघात की स्थिति से स्पष्ट होता है। भारत इन चुनौतियों का सामना बुनियादी ढांचे में सुधार और मजबूत बफर के साथ कर रहा है। भविष्य में सतत संवृद्धि बनाए रखने के लिए निजी निवेश में प्रोत्साहन एक महत्वपूर्ण पक्ष बना हुआ है जिसपर जोर देने की आवश्यकता है।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, जिसमें बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण दृष्टिकोण अस्पष्ट है। अवरुद्ध आपूर्ति और कमोडिटी - विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा - की बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा गया है और इसके कारण केंद्रीय बैंकों के लिए नीतिगत संतुलन बनाना कठिन हो गया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के बहिर्वाह और मुद्रा मूल्यहास के अलावा, विघटनकारी प्रसार-प्रभाव के कारण वित्तीय बाजार की स्थिति कठिन बनी हुई है। इन अस्थिर स्थितियों के मद्देनजर, निवेशक युद्ध समाप्ति से जुड़ी सकारात्मक खबरों से जुड़े जोखिम के स्वरूप के विकल्पों को देखते हुए छिटपुट रूप से सुरक्षित-संपत्तियों के आश्रय की तलाश कर रहे हैं। नतीजतन, वित्तीय बाजार क्षुब्ध हैं।

भारत भी इन घटनाक्रमों से झटके महसूस कर रहा है। युद्ध और प्रतिशोधी प्रतिबंधों का नतीजा, मुद्रास्फीति प्रिंट और

भुगतान संतुलन से जुड़ी गतिविधियों में पहले ही स्पष्ट है। बहरहाल, कुछ घरेलू कारक कुछ हद तक राहत प्रदान करते हैं। जैसे ही भारत संवत् 2079¹ में प्रवेश करता है, तीसरी लहर खासा पीछे छूट गई लगती है और टीकाकरण कवरेज के विस्तार के साथ-साथ सभी प्रतिबंधों के हटने के कारण, आर्थिक गतिविधि गति पकड़ रही है। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र महामारी-पूर्व के स्तर तक पहुंच रहे हैं या पार कर चुके हैं। विशेष रूप से, बैंक ऋण ने गति पकड़ ली है और रोजगार बाजार में तेजी आ रही है। यात्रा और आतिथ्य क्षेत्रों में तेजी आई है। निर्माण और रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी दर्ज की गई है।

8 अप्रैल 2022 की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारत में मौद्रिक नीति के संचालन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसा कि गवर्नर, श्री शक्तिकांत दास के वक्तव्य में उसी दिन कहा गया है, भू-राजनीतिक तनाव में तेज वृद्धि ने बाहरी और घरेलू परिदृश्य को काफी बदल दिया है। वैश्विक मुद्रास्फीति प्रमुख देशों में लक्ष्य से काफी ऊपर चल रही है और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हाल के घटनाक्रमों और उभरते दृष्टिकोण को देखते हुए, एमपीसी ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। हालाँकि, कई उल्लेखनीय विशेषताएं इस यथास्थिति को अलग करती हैं। सबसे पहले, पूर्वानुमान - जो मौद्रिक नीति के मध्यवर्ती लक्ष्यों के रूप में कार्य करते हैं - में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। फरवरी 2022 की स्थिति के सापेक्ष 2022-23 के लिए अनुमानित औसत मुद्रास्फीति में 120 आधार अंकों (5.7 प्रतिशत तक) की वृद्धि हुई और संवृद्धि में 60 आधार अंकों (7.2 प्रतिशत तक) की कमी आई है जो भू-राजनीतिक संघर्ष के प्रभाव को दर्शाता है। दूसरा, इस दृष्टिकोण के अनुरूप, एमपीसी ने अपने उद्देश्यों के बीच मूल्य स्थिरता को पुनः प्राथमिकता दी "यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि में सहायक होकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे"। तीसरा, एमपीसी ने नरम रुख बनाए रखने लेकिन अनुमानों के साथ तालमेल बिठाने और नीतिगत उद्देश्यों के पुनर्क्रम में "नरम रुख को वापस लेने पर" ध्यान केंद्रित करने का

इस आलेख को शाहबाज खान, शशिधर एम. लोकरे, कुणाल प्रियदर्शी, राजीव जैन, विनीत कुमार श्रीवास्तव, बरखा गुप्ता, प्रियंका सचदेव, प्रशांत कुमार, ऋषभ कुमार, सक्षम सूद, सत्यम कुमार, दीपिका रावत, जिबिन जोस, सत्यार्थ सिंह, सुधांशु गोयल, युवराज कश्यप, आशीष संतोष खोब्रागड़े, शैलजा भाटिया, देब प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा ने तैयार किया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को व्यक्त करते हों।

¹ हिन्दू नववर्ष।

फैसला किया। चौथा, आरबीआई ने खंड IV में निर्धारित एमपीसी के निर्णय को लागू करने के लिए मौद्रिक नीति की संचालन प्रक्रिया में नवीन परिशोधन की घोषणा की।

इससे पहले कि हम वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों की ओर मुड़ें, चिंता का एक क्षेत्र है- वर्तमान में प्रचंड गर्मी की लहरा देश के कई हिस्सों में तापमान अब तक का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरे देश ने पिछले 122 वर्षों में सबसे गर्म मार्च (औसत अधिकतम तापमान) देखा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, माना जाता है कि यह बेमौसम घटना पश्चिमी भारत में प्रति-चक्रवातीय प्रवाह की अग्रिम शुरुआत और मध्य राज्यों में कम बारिश के कारण हुई है। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि गर्मी की इन लहरों का अप्रैल के मध्य से आगे भी जारी रहने की संभावना है। इन बेमौसम उतार-चढ़ावों की बढ़ती आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रकट करती है और कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी और विकास रणनीतियों में प्रासंगिक जलवायु चर को एकीकृत करने की तात्कालिकता की ओर ध्यान दिलाती है।

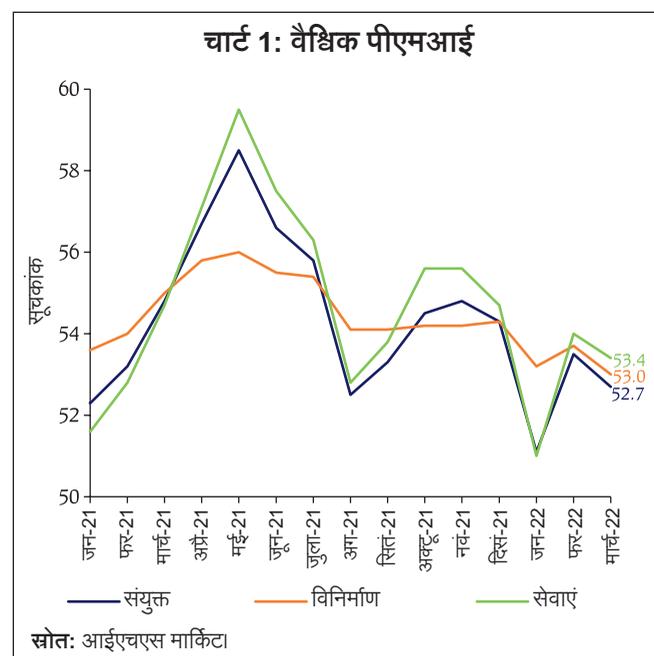
इस पृष्ठभूमि में, शेष लेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल करता है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में किया गया है। खंड IV में भारत में वित्तीय स्थितियों को शामिल किया गया है, जबकि अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

II. वैश्विक परिदृश्य

भू-राजनीतिक शत्रुता और उनके प्रभाव वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर भारी पड़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतें, जो पहले से ही मांग-आपूर्ति असंतुलन के बीच ऊपर की ओर बढ़ रही थीं, मार्च 2022 की शुरुआत में अधिक हो गईं और उसके बाद ऊंचे स्तरों पर अस्थिर बनी रहीं। उच्च पण्य कीमतों का संचरण दर्शाते हुए, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति नए रिकॉर्ड स्तरों तक और बढ़ गई, जिससे केंद्रीय बैंकों को संवृद्धि के प्रति बढ़ते जोखिमों के बावजूद उदार मौद्रिक नीति रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ा।

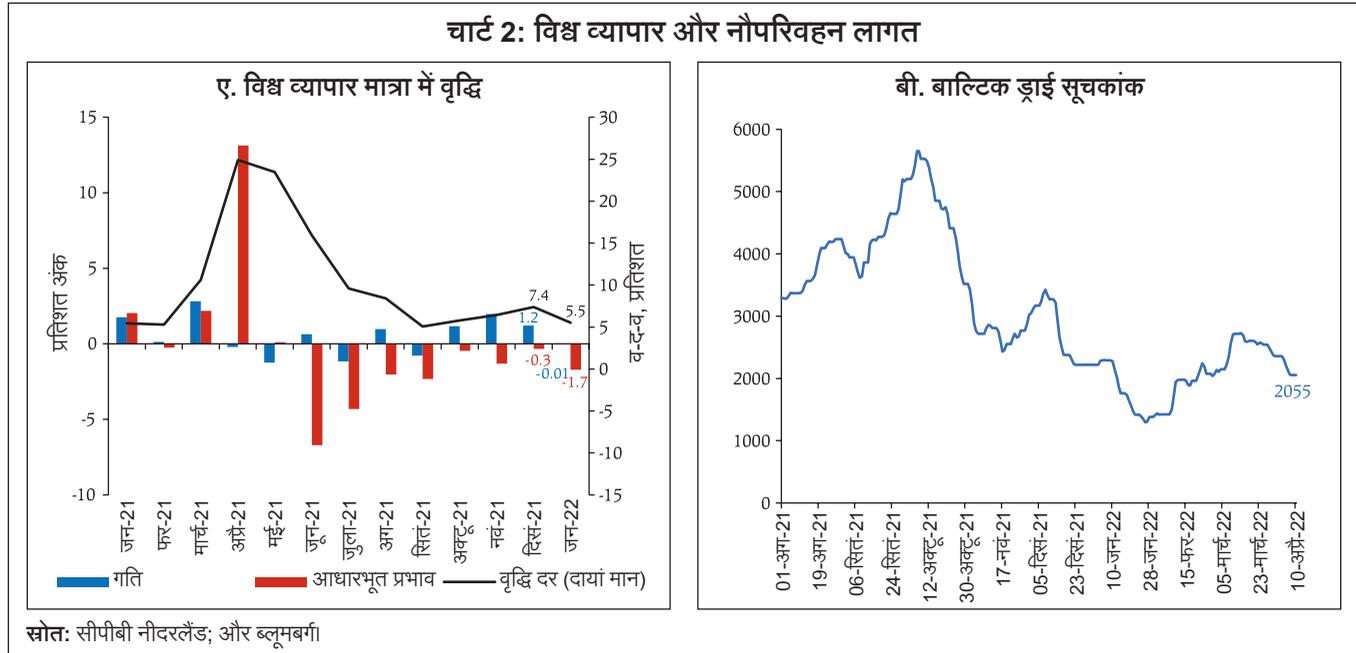
17 मार्च 2022 को जारी अपने अंतरिम आर्थिक आउटलुक में ओईसीडी ने वैश्विक संवृद्धि में अपने दिसंबर के 4.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान से 2022 में 1 प्रतिशत अंक की कमी का अनुमान लगाया है। यह अधोमुखी संशोधन मानता है कि संघर्ष के पहले दो हफ्तों में देखे गए कमोडिटी और वित्तीय बाजार के झटके कम से कम एक साल तक बने रहेंगे। इसी तरह की चिंताओं को दर्शाते हुए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) की व्यापार और विकास रिपोर्ट 24 मार्च 2022 को जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वैश्विक संवृद्धि 3.6 प्रतिशत² के अंकुश के पूर्वानुमान से 1 प्रतिशत अंक घटकर 2.6 प्रतिशत हो जाएगा जो लगभग यूएस \$1 ट्रिलियन पूर्वनिश्चित आय की राशि के बराबर है। यह इस आकलन पर आधारित है कि प्रतिबंध और आपूर्ति शृंखला व्यवधान 2022 तक चलेगा भले ही युद्ध समाप्त हो जाए।

उच्च आवृत्ति संकेतकों के बीच, वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मार्च में एक महीने पहले 53.5 से घटकर 52.7 पर आ गया, जो भू-राजनीतिक तनाव और कोविड एवं आपूर्ति शृंखलाओं के कारण व्यवधानों में कमी का संकेत देता है (चार्ट 1)। सेवाओं और विनिर्माण दोनों पीएमआई कम हुए, बाद वाला 18 महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि आउटपुट में



² अंकटाड का वैश्विक संवृद्धि अनुमान बाजार विनिमय दर पर स्थिर अमेरिकी डॉलर पर मापा जाता है, जबकि ओईसीडी का संवृद्धि अनुमान क्रय शक्ति समता भारित कुल पर है।

चार्ट 2: विश्व व्यापार और नौपरिवहन लागत

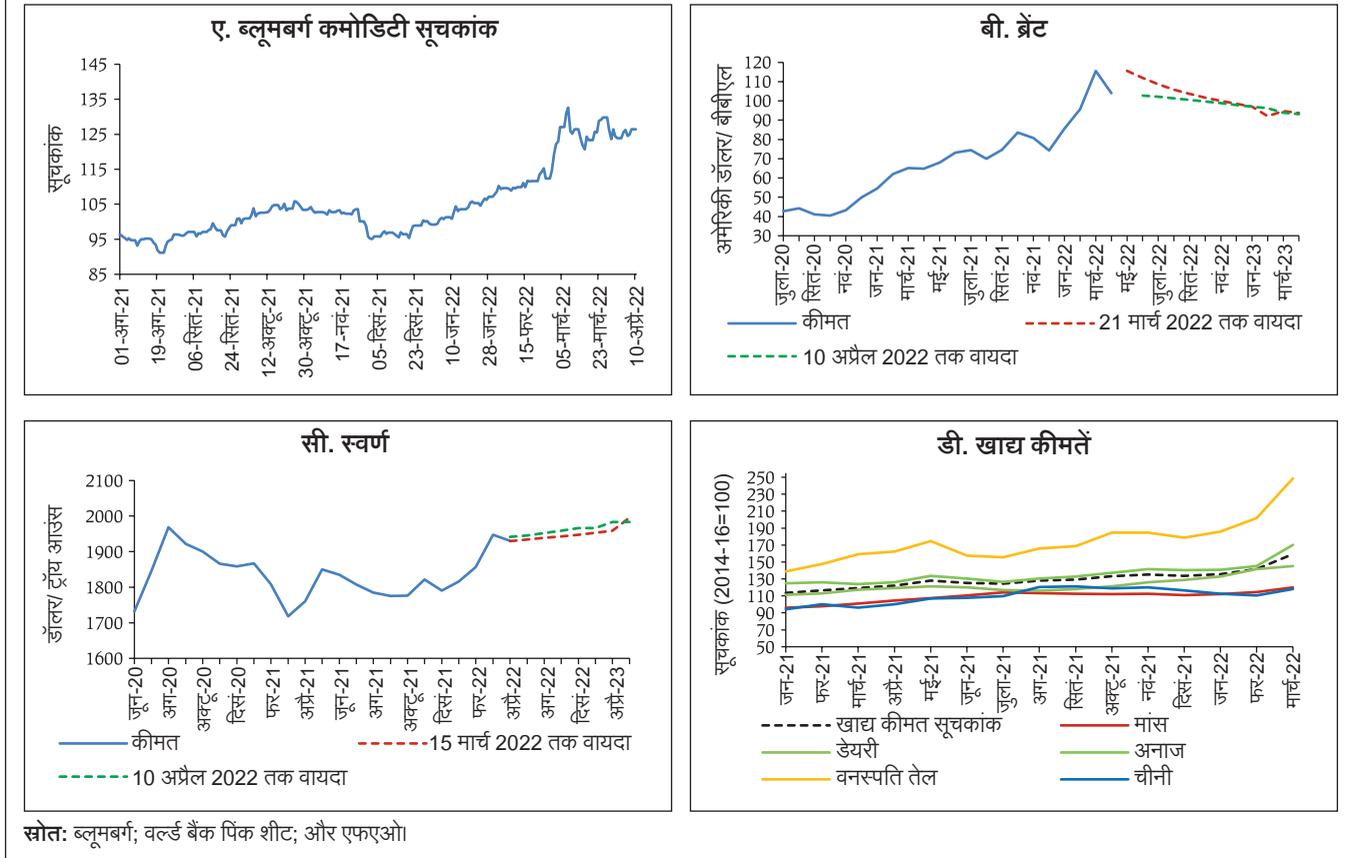


वृद्धि और नए ऑर्डर धीमे हो गए जबकि नए निर्यात कारोबार में कमी आई। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थिति अच्छी रही जबकि चीन और रूस ने अपने समग्र पीएमआई में संकुचन दर्ज किया, बाद में मई 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

सीपीबी वर्ल्ड ट्रेड मॉनिटर का मासिक डेटा लगातार तीन महीनों की गति (चार्ट 2ए) के बाद जनवरी 2022 में विश्व व्यापार की मात्रा में 5.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर, चीन सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने आयात और निर्यात (-2.7 प्रतिशत और -1.5 प्रतिशत) दोनों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की, लेकिन यूरो क्षेत्र में व्यापार में तेजी आई। अंकटाड ने एशिया- यूरोप समुद्री माल-दुलाई मांग में 5-8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कीमतों के दबाव को और बढ़ा सकता है। ब्लैक सी-मेड अफ्रामैक्स और स्वेजमैक्स टैंकर माल भाड़ा दरों में 400 प्रतिशत की वृद्धि के शुरुआती संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो मार्च 2022 में नए सिरे से आपूर्ति व्यवधानों के बीच उच्च बना रहा, अप्रैल में अब तक (10 अप्रैल तक) (चार्ट 2बी) कुछ हद तक कम हो गया है।

युद्ध-प्रेरित आपूर्ति झटके (चार्ट 3ए) के कारण चारों ओर कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स मार्च की शुरुआत में 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। मार्च के मध्य से, हालांकि, यह दो-तरफा परिवर्तन दिख रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतें 14 साल के उच्चम स्तर 133 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं (चार्ट 3बी)। यद्यपि वे बाद में कम हो गईं लेकिन उच्च अस्थिरता बनी रही। अमेरिका द्वारा अपने रणनीतिक तेल भंडार से 180 मिलियन बैरल जारी करने की घोषणा ने मार्च के अंत तक लाभ सीमित कर दिया। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रही हैं, जो 2022 में अब तक (10 अप्रैल तक) 31.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज कर रही है। सुरक्षित आश्रय और मुद्रास्फीति से बचाव की अपील को देखते हुए, सोने की कीमतों में भी फरवरी के बाद से तेजी आई है। हालांकि मार्च के उत्तरार्ध में बॉन्ड यील्ड कम होने पर कीमतों में मजबूती आई, पीली धातु ने शुद्ध लाभ (चार्ट 3सी) के साथ महीने का अंत किया। बेस मेटल की कीमतों ने भी इसी तरह की प्रवृत्ति प्रदर्शित की, जिसमें निकल, एल्यूमीनियम और पैलेडियम - रूस-यूक्रेन के प्रमुख निर्यात - सबसे अधिक बढ़ रहे हैं। मार्च में एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक 159.3 पर रिकॉर्ड पर उच्चतम मासिक उछाल के

चार्ट 3: जिंस (कमोडिटी) और खाद्य की कीमतें



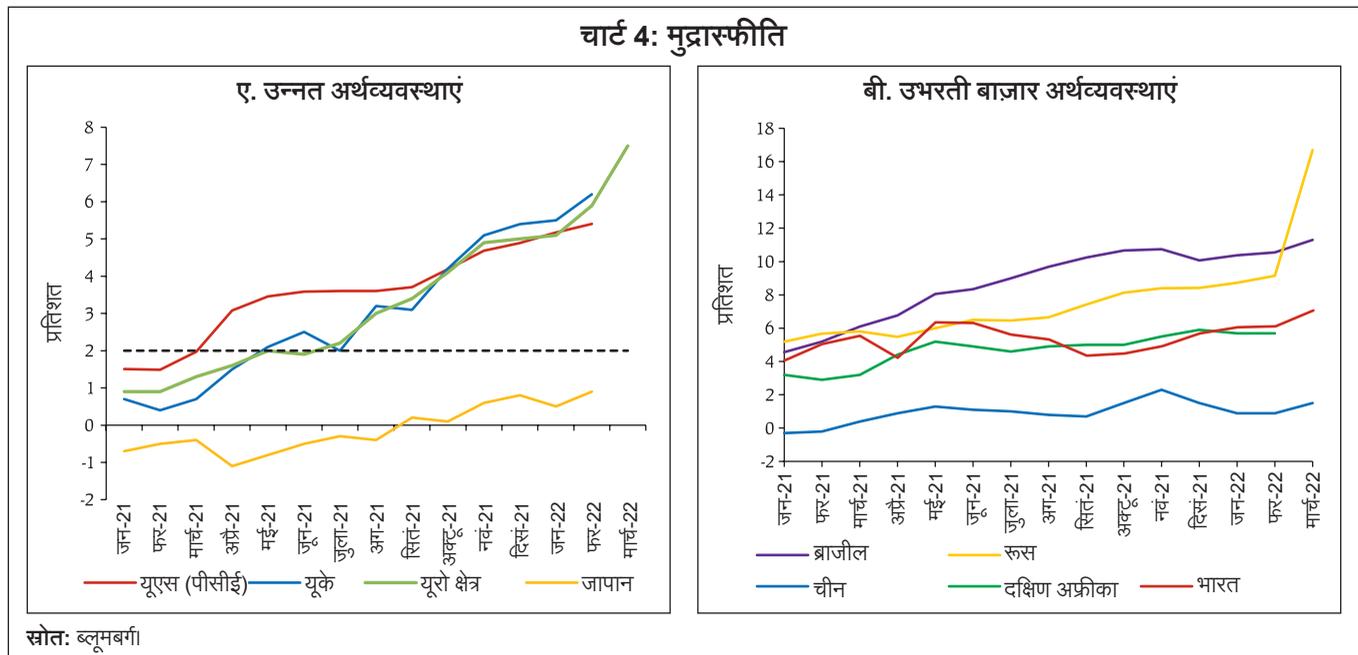
साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वृद्धि चारों ओर देखी गई, वनस्पति तेल और अनाज उप-सूचकांक अधिकतम गति (चार्ट 3डी) प्रदर्शित करते हैं।

मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्थाओं में अधिक मजबूत और व्यापक हो रही है। चल रहे भू-राजनीतिक संकट और लंबे समय तक आपूर्ति में व्यवधान के डर ने मुद्रास्फीति के जोखिम को बढ़ा दिया है। तदनुसार, ओईसीडी ने वैश्विक मुद्रास्फीति के अनुमान को 2022 के लिए अपने दिसंबर के 4.2 प्रतिशत के अनुमान से लगभग 2.5 प्रतिशत अंक संशोधित किया है। यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति मार्च में 7.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो फरवरी में 5.9 प्रतिशत थी, क्योंकि ऊर्जा और खाद्य कीमतों में युद्ध के कारण व्यवधानों (चार्ट 4ए) से तेजी आई थी। अमेरिकी व्यक्तिगत खपत व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति फरवरी में 6.4 प्रतिशत के नए रिकॉर्ड तक पहुंच गई, जो ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है। मूल

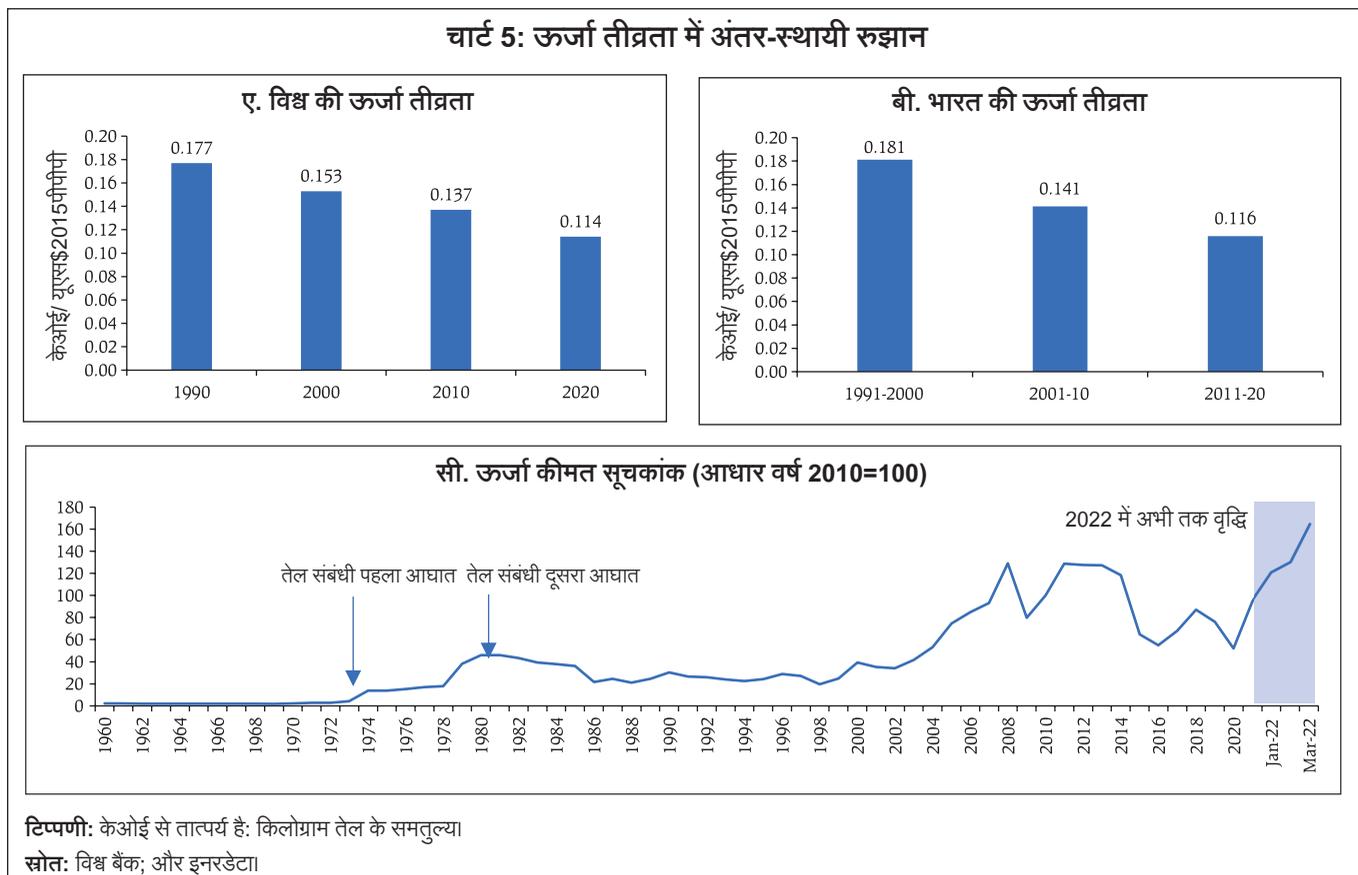
पीसीई मुद्रास्फीति भी 39 साल के उच्च स्तर पर बनी रही। यूके में, मुद्रास्फीति ने फरवरी में 6.2 प्रतिशत का एक नया रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि ऊर्जा, खाद्य और टिकाऊ वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण कीमतों का दबाव अधिक व्यापक हो गया। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं- ब्राजील में मार्च में मुद्रास्फीति 11.3 प्रतिशत पर लगातार सातवें महीने दोहरे अंकों में रही, जबकि चीन में यह तीन महीने के उच्च स्तर 1.5 प्रतिशत (चार्ट 4बी) पर पहुंच गई। रूस में, प्रतिबंधों और रूबल में तेज मूल्यहास के बाद, मुद्रास्फीति- 2015 के बाद पहली बार - फरवरी में 9.2 प्रतिशत से मार्च में 16.7 प्रतिशत के दोहरे अंकों के आंकड़े पर पहुंच गई।

विश्व स्तर पर, ऊर्जा की तीव्रता ने गिरावट का रुख दिखाया है, जिसका अर्थ है कि पिछले कुछ वर्षों में इसके उपयोग की दक्षता में वृद्धि हुई है (चार्ट 5ए) ³। भारत की ऊर्जा गहनता में भी

³ ऊर्जा की तीव्रता मापती है कि जीडीपी के प्रत्येक डॉलर का उत्पादन करने के लिए अर्थव्यवस्था कितनी कुशलता से ऊर्जा का उपयोग करती है।



एक निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, जिसका अर्थ है कि अन्य बातों के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के उत्पादन ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन चल रहे हैं (चार्ट 5बी)।



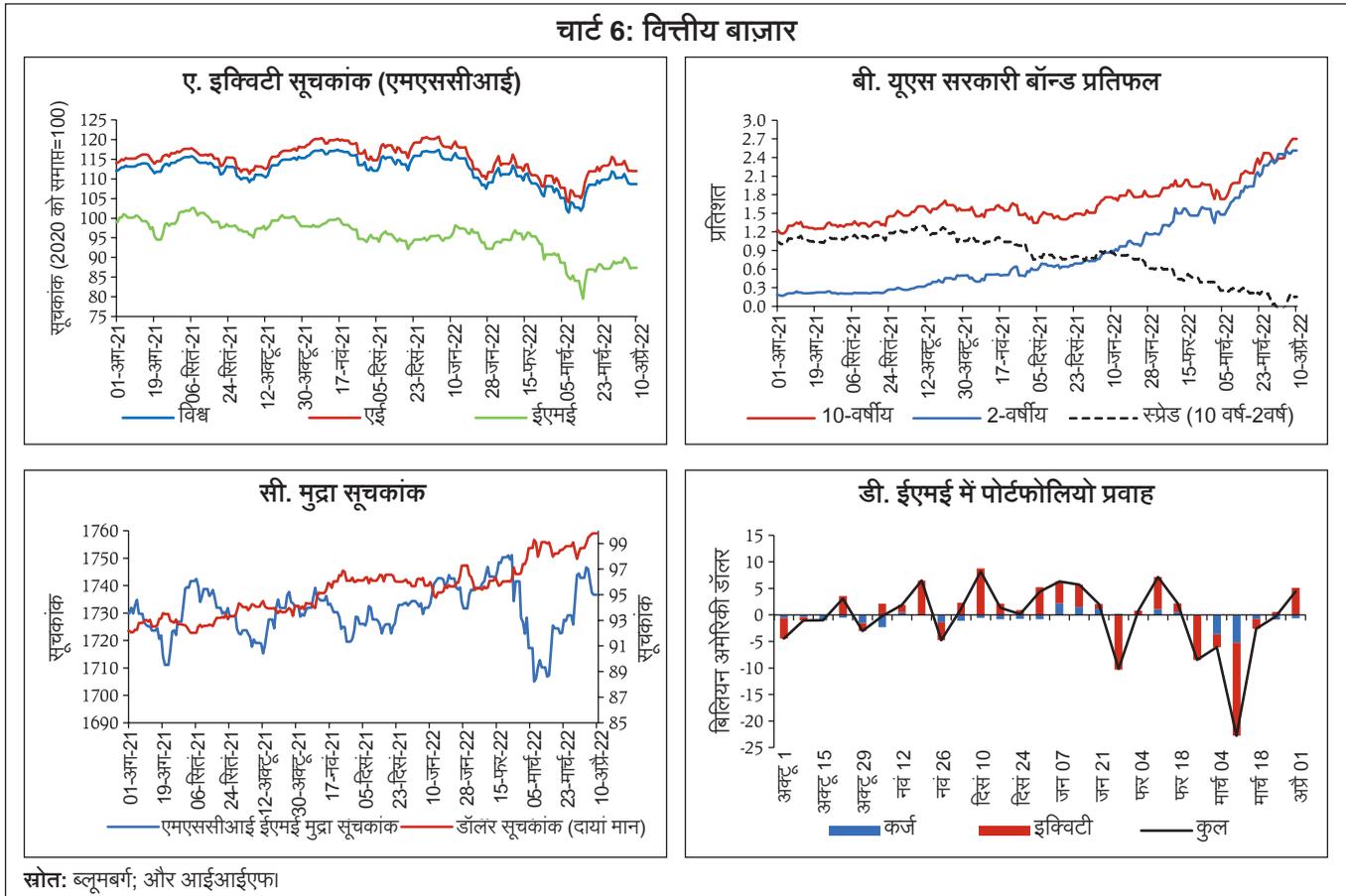
वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल की मार पड़ी क्योंकि युद्ध-प्रेरित अनिश्चितताओं और नीति के सामान्यीकरण ने निवेशकों को अनिश्चय में रखा। मार्च के मध्य तक वैश्विक इक्विटी बाजारों में गिरावट आई, लेकिन उन्होंने घाटे की भरपाई की और मार्च में 2 प्रतिशत का मासिक लाभ अर्जित किया (चार्ट 6ए), उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों में अधिकांश स्टॉक इंडेक्स 2022 में अब तक (10 अप्रैल तक) ऋणात्मक प्रतिफल दे रहे हैं जिसके कारण एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स साल-दर-साल आधार पर लाल रंग में है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच, यूएस एसएंडपी स्टॉक इंडेक्स ने मार्च में शुद्ध लाभ के साथ समाप्ति दर्ज की क्योंकि उत्साहित आर्थिक डेटा और युद्धविराम आशावाद ने जोखिम लेने की भावनाओं को मजबूत किया और मार्च की शुरुआत में बिकवाली की भरपाई की। ईएमई शेयरों ने अपने ईई समकक्षों से कम प्रदर्शन किया, चीनी स्टॉक सूचकांकों ने मार्च में सबसे खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि विभिन्न शहरों और विनिर्माण

सुविधाओं के बंद होने के बीच बढ़ते संक्रमणों ने वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित किया।

बांड बाजारों में, 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल, जिसमें क्षणिक बढ़ोतरी हुई थी मार्च के मध्य से कम हो गया। तेजी से दर वृद्धि में बाजार मूल्य निर्धारण के कारण अल्पकालिक प्रतिफल में उछाल आया, जिससे 10-वर्ष से 2-वर्ष खंड (चार्ट 6बी) के प्रतिफल स्प्रेड में एक अल्पकालिक उलटफेर हुआ।

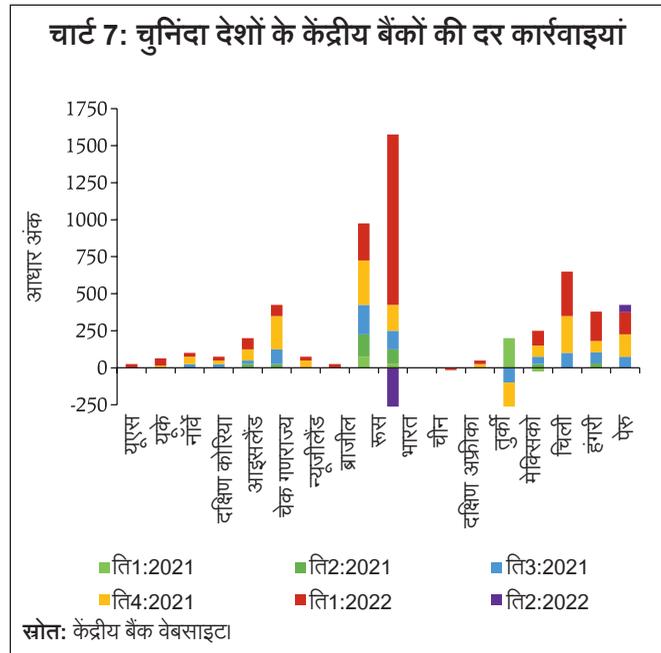
मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर ने मार्च के मध्य से दोतरफा परिवर्तन प्रदर्शित किया। बाजार की भावनाओं में उतार-चढ़ाव उच्च अस्थिरता (चार्ट 6सी) प्रदान कर सकता है। साथ ही, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी इंडेक्स मार्च की पहली आधी अवधि में भारी गिरावट के बाद उपर चढ़ा जिसके कारण मुख्य रूप से कुछ प्रमुख कमोडिटी निर्यातकों की मुद्राओं में मजबूती आई और महीने के बाद के हिस्से में ईएमई (चार्ट 6डी) में पूंजी बहिर्वाह घटा।

चार्ट 6: वित्तीय बाजार



विश्व स्तर पर, अलग-अलग गति से मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और नीतियों को प्रोत्साहन और सामान्यीकरण को समाप्त करने की ओर लक्षित किया गया है। मार्च 2018 की अपनी बैठक में यूएस फेड ने दिसंबर 2018 के बाद से अपनी पहली दर वृद्धि को प्रभावित किया, फेडरल फंड्स दर के लिए लक्ष्य सीमा को 25 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 0.25-0.5 प्रतिशत कर दिया, जबकि बैलेंस शीट में कमी भी की। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मौद्रिक नीति को सख्त करना जारी रखा, मार्च में अपनी नीति दर में 25 बीपीएस की वृद्धि की – जो बेंचमार्क ब्याज दर को 0.75 प्रतिशत तक ले जाने वाली लगातार तीसरी वृद्धि थी। अन्य एई में, नोर्गेस बैंक ने 2021 में दो दर वृद्धि के बाद दरों में फिर से 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की। ईएमई के बीच, ब्राजील ने अपनी नीतिगत दर को और 100 बीपीएस बढ़ा दिया, जिससे इसके सख्ती वाले चक्र के एक वर्ष में कुल संचयी वृद्धि 975 बीपीएस हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दर को लगातार तीसरी बार 25 बीपीएस तक बढ़ाया, नवंबर 2021 से कुल वृद्धि को बढ़ाकर 75 बीपीएस कर दिया। अन्य ईएमई में, चिली, हंगरी और मैक्सिको ने मार्च में अपनी बेंचमार्क दरों में क्रमशः 150 बीपीएस, 100 बीपीएस और 50 बीपीएस की वृद्धि की। दूसरी ओर, चीन और तुर्की ने मार्च में क्रमशः अपनी दूसरी और तीसरी लगातार बैठकों में यथास्थिति बनाए रखी। फरवरी के अंत में 10.5 प्रतिशत अंक की आपातकालीन दर में वृद्धि के बाद बैंक ऑफ रूस ने अपनी वित्तीय प्रणाली (चार्ट 7) में स्थिरीकरण के संकेतों के बाद 08 अप्रैल 2022 को एक अनिर्धारित बैठक में अपनी नीतिगत दर को 300 बीपीएस से घटाकर 17 प्रतिशत कर दिया।

वैश्विक परिदृश्य भू-राजनीतिक ताकतों के प्रसार-प्रभाव में बना हुआ है। आगे चलकर, उच्च अस्थिरता के कारण जोखिम से बचने की भावना ने वित्त बाजार में अस्थिरता पैदा की जिसका असर आर्थिक गतिविधि पर पड़ा। इसके अलावा, दबावग्रस्त आपूर्ति और वस्तुओं की कीमतों में सहवर्ती वृद्धि के कारण, मुद्रास्फीति के आंकड़े नई उंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, इस प्रकार, नीति निर्माताओं के लिए उच्च ब्याज दरों के साथ संवृद्धि की गति को सुस्त किए बिना बढ़ रही मुद्रास्फीति के दबावों को कम करना मुश्किल कार्य बना हुआ है।



III. घरेलू घटनाक्रम

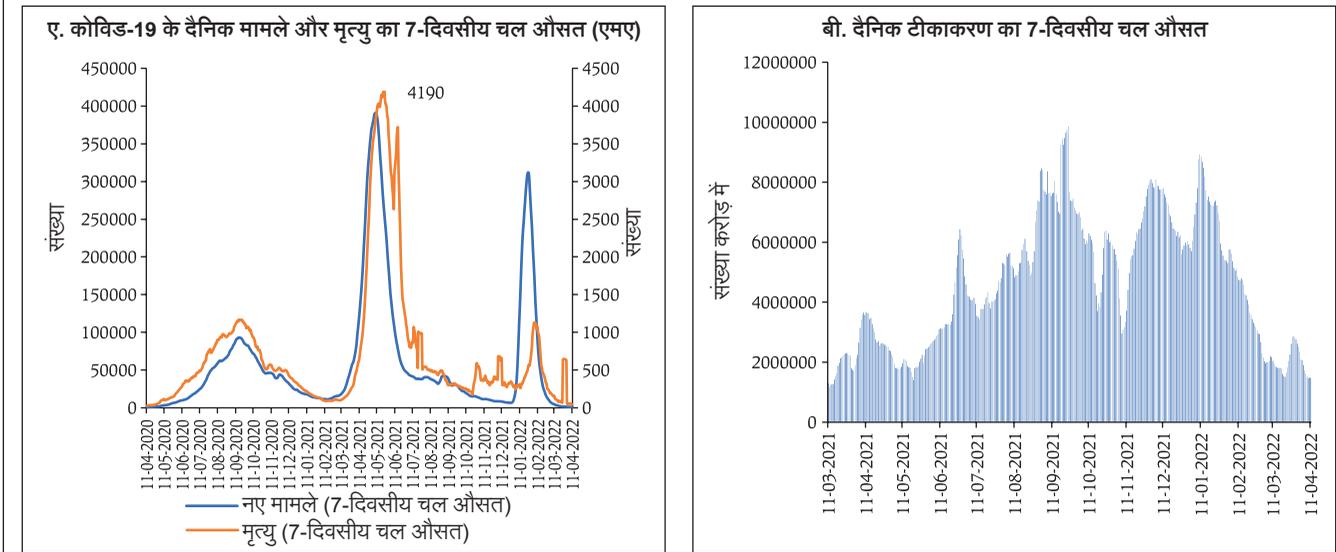
कोविड-19 संक्रमणों में तीव्र कमी और कामकाज के सामान्य तरीकों में आर्थिक गतिविधियाँ फिर से शुरू होने के कारण घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार होना शुरू हो गया है। 20 जनवरी 2022 (चार्ट 8ए) को 3.47 लाख के शिखर-स्तर से 11 अप्रैल 2022 को दैनिक संक्रमण गिरकर 861 हो गया। इसी अवधि के दौरान दैनिक पॉज़िटिविटी दर 17.94 प्रतिशत से घटकर 0.32 प्रतिशत हो गई।

84 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी (80 करोड़) और 15-18 वर्ष आयु वर्ग के 3.9 करोड़ से अधिक बच्चों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 12-14 वर्ष आयु वर्ग के 2.2 करोड़ बच्चों को पहली खुराक दी गई है। 11 अप्रैल 2022 (चार्ट 8बी) तक टीकाकरण की कुल खुराक 185 करोड़ को पार कर गई है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 से फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता⁴ को छोड़कर, सभी कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को हटा दिया है।

मॉबिलिटी पूर्व-कोविड स्तरों से काफी ऊपर बनी हुई है। एक महीने पहले की तुलना में अप्रैल (11 अप्रैल 2022 तक) में सभी श्रेणियों में गुगल की मॉबिलिटी में सुधार हुआ, जो किराना, फार्मसी

⁴ https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ChiefSecretaries_23032022.pdf

चार्ट 8: कोविड-19 के दैनिक मामले और टीकाकरण

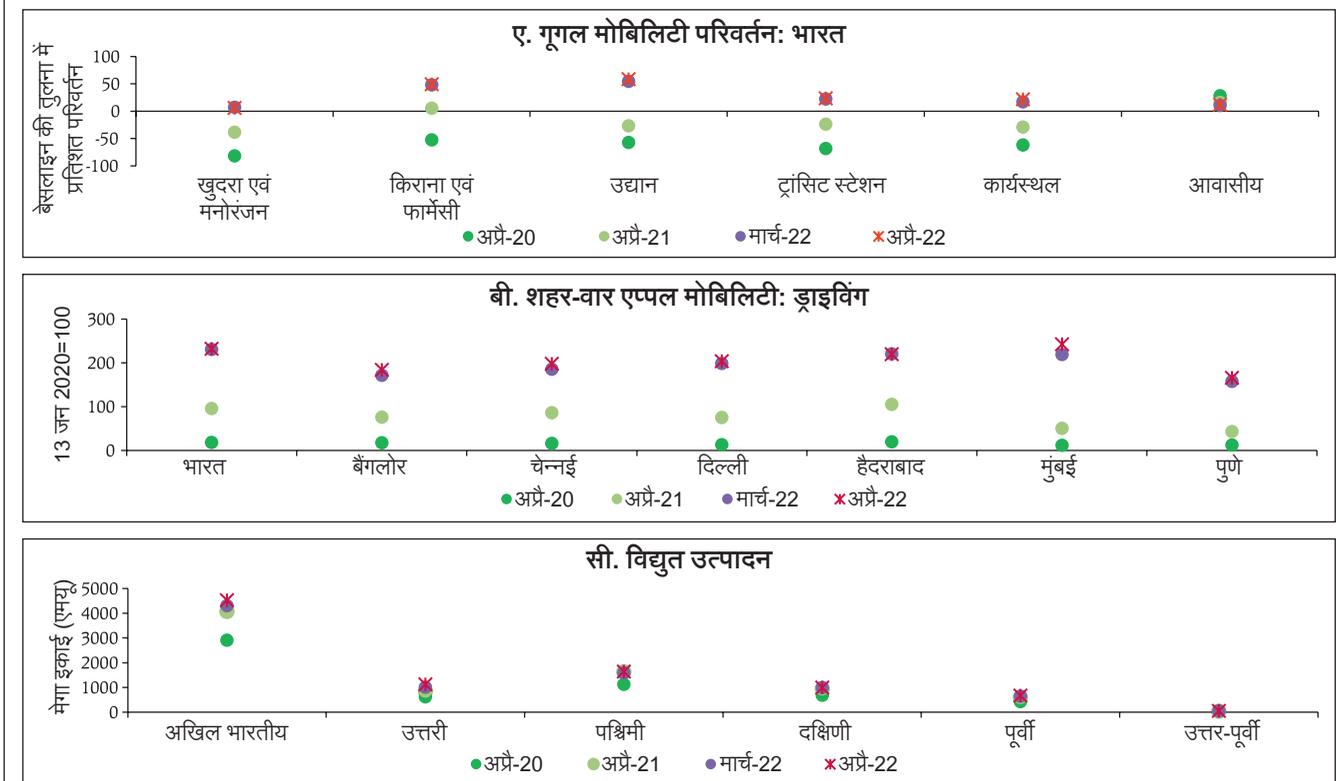


स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू)

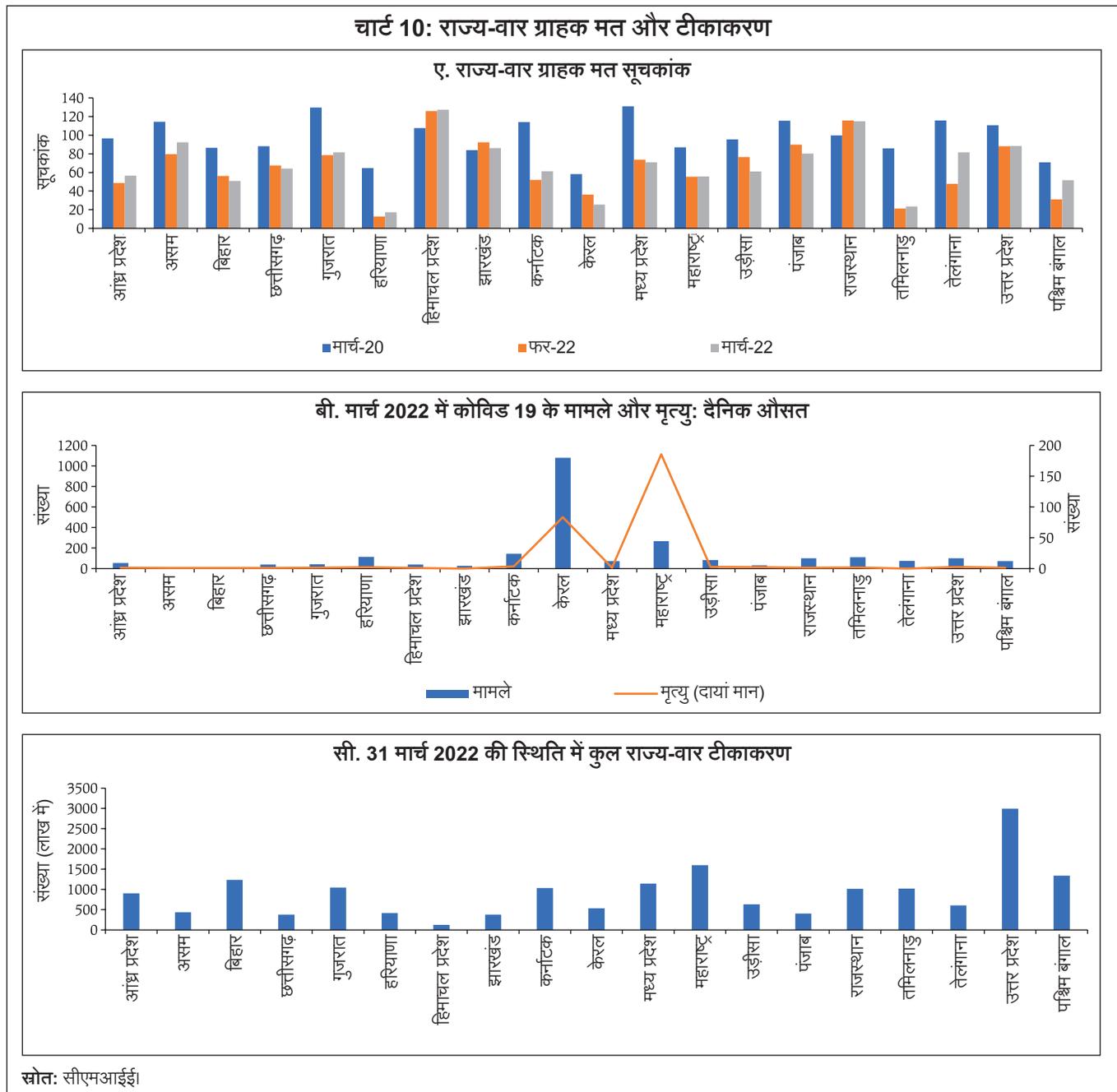
और पार्को (चार्ट 9ए) के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। एपल मॉबिलिटी इंडेक्स ने भी अप्रैल (चार्ट 9बी) में मजबूत सुधार दर्ज किया। सेवा क्षेत्र के आउटलेट के खुलने के साथ,

अप्रैल में सभी क्षेत्रों में बिजली उत्पादन में तेजी आई, जो पूर्व-महामारी स्तर और एक महीने पहले दर्ज किए गए स्तरों को पार कर गया (चार्ट 9सी)।

चार्ट 9: आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 की तीसरी लहर का प्रभाव



स्रोत: गूगल; सीईआईसी; और पीओएसओसीओ



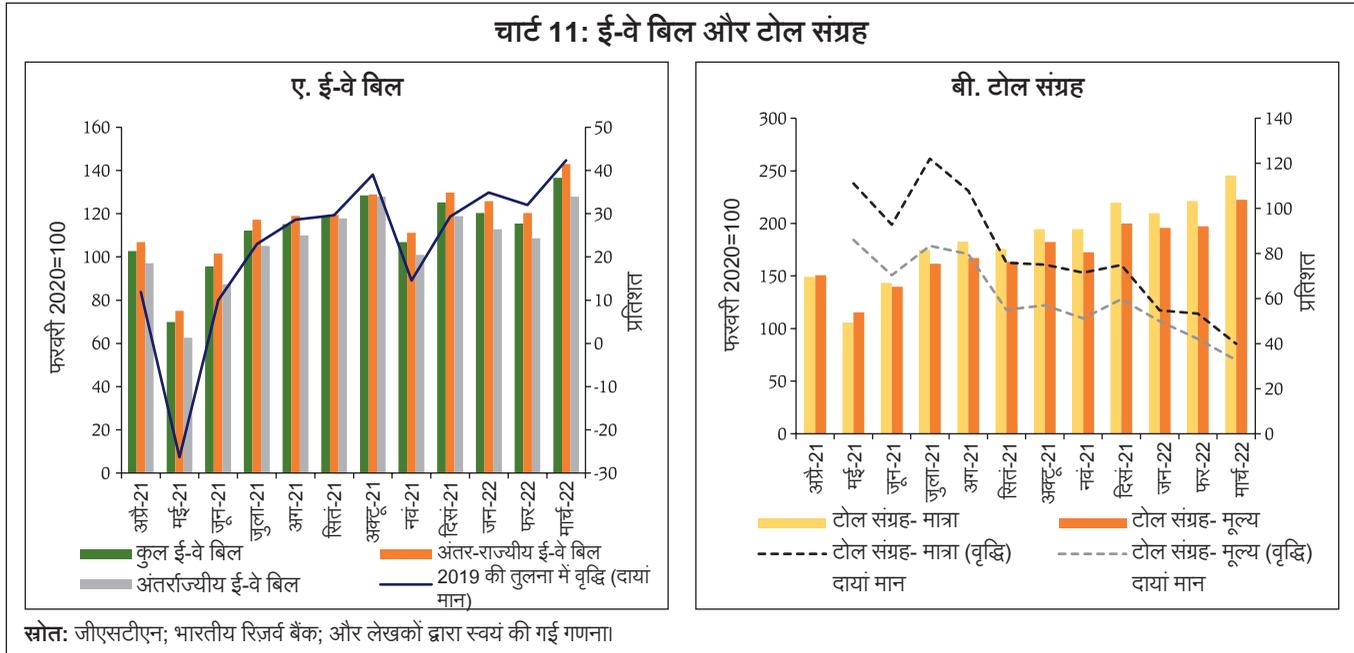
इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप, मार्च में अधिकांश राज्यों में उपभोक्ता के रुख में क्रमिक रूप से सुधार हुआ (चार्ट 10)।

कुल मांग

मार्च 2022 में ई-वे बिल 48 महीने के उच्च और महामारी पूर्व स्तर से 37 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड करने के साथ, कुल

मांग के संकेतक उपर आ गए। वृद्धि में इंटर-स्टेट ई-वे बिल (चार्ट 11 ए) सबसे आगे रहा। मार्च में टोल संग्रह लगातार चौथे महीने (चार्ट 11 बी) के लिए पूर्व-महामारी स्तर से दोगुना हो गया।

चार्ट 11: ई-वे बिल और टोल संग्रह



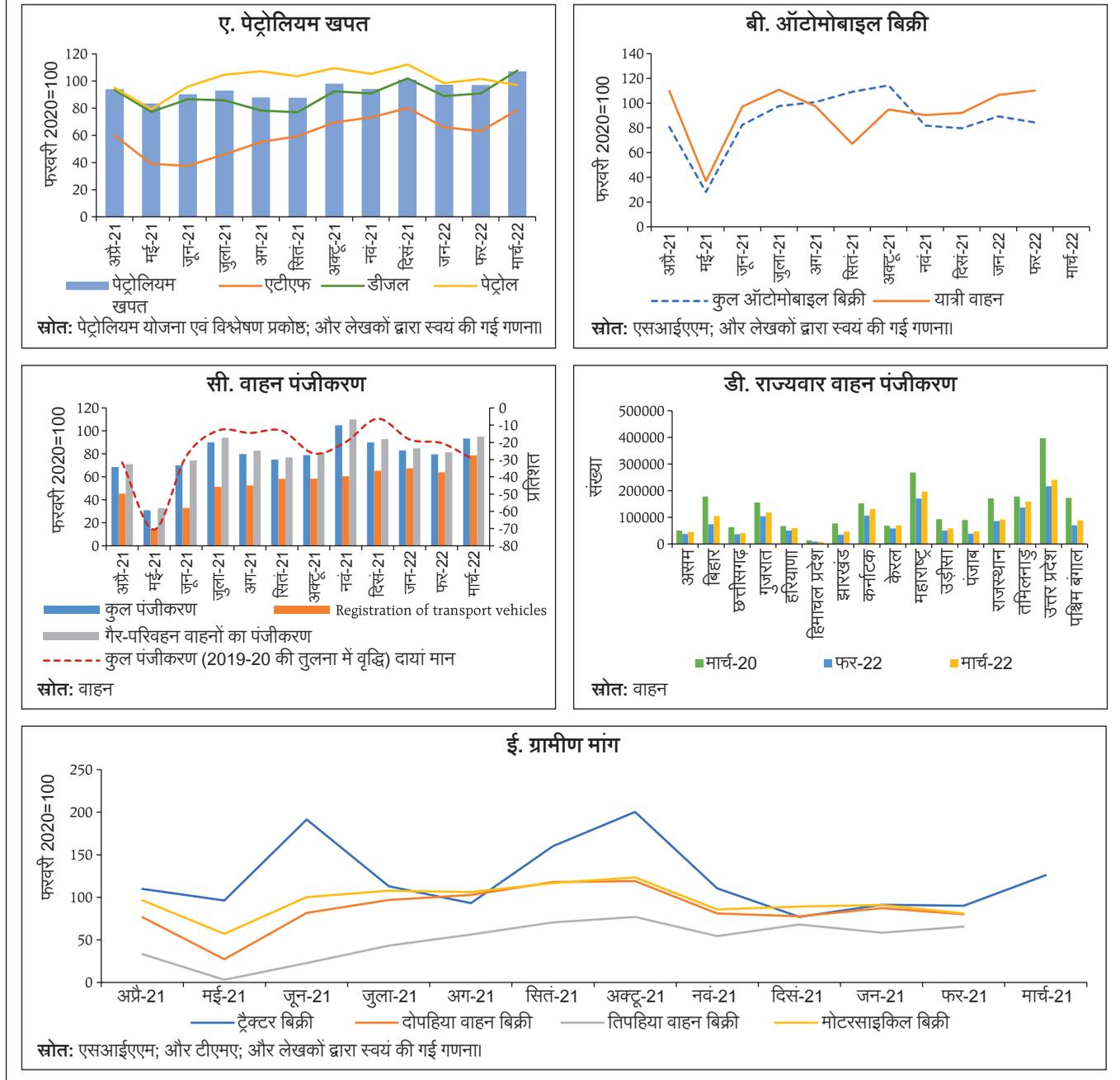
कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ईंधन की खपत में सुधार हुआ क्योंकि मांग में सुधार हुआ। विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) और डीजल की खपत में क्रमिक रूप से सुधार हुआ। लेकिन उच्च ईंधन मुद्रास्फीति के कारण पेट्रोल की खपत में कमी आई (चार्ट 12ए)।

दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट के कारण मार्च में ऑटोमोबाइल की बिक्री कम रही, यहां तक कि मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से यात्री वाहनों के थोक प्रेषण में निरंतर मांग गति (चार्ट 12 बी) के साथ वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री सपाट रहने की उम्मीद है क्योंकि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से मांग में कमी आ सकती है। परिवहन वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री बढ़ी (चार्ट 12सी)। मार्च में वाहन पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो राज्य शीर्ष पर थे (चार्ट 12डी)। इलेक्ट्रिक वाहन हिस्सा अन्य क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन कर

रहा है, लेकिन नीकेल जैसे प्रमुख कच्चे माल की कमी से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी के लिए इनपुट लागत बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह, सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त दुर्लभ-पृथ्वी धातुओं और नियॉन गैस की आपूर्ति व्यवधानों की चपेट में है। ग्रामीण मांग के भीतर, ट्रैक्टर की बिक्री मार्च 2022 में मजबूत क्रमिक वृद्धि दर्शाती है (चार्ट 12ई)।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, श्रम भागीदारी दर फरवरी में 39.9 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2022 में 39.5 प्रतिशत हो गई। रोजगार दर (श्रमिक जनसंख्या अनुपात) में 20 आधार अंकों की गिरावट आई, लेकिन मार्च में बेरोजगारी दर गिरकर 7.6 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 8.1 प्रतिशत थी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर एक प्रतिशत से अधिक गिर गई, यह शहरी क्षेत्रों में बढ़ी (चार्ट 13 ए)। हालांकि अधिकांश राज्यों में फरवरी की तुलना में मार्च में रोजगार दरों में कमी देखी गई, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया

चार्ट 12: परिवहन क्षेत्र संकेतक



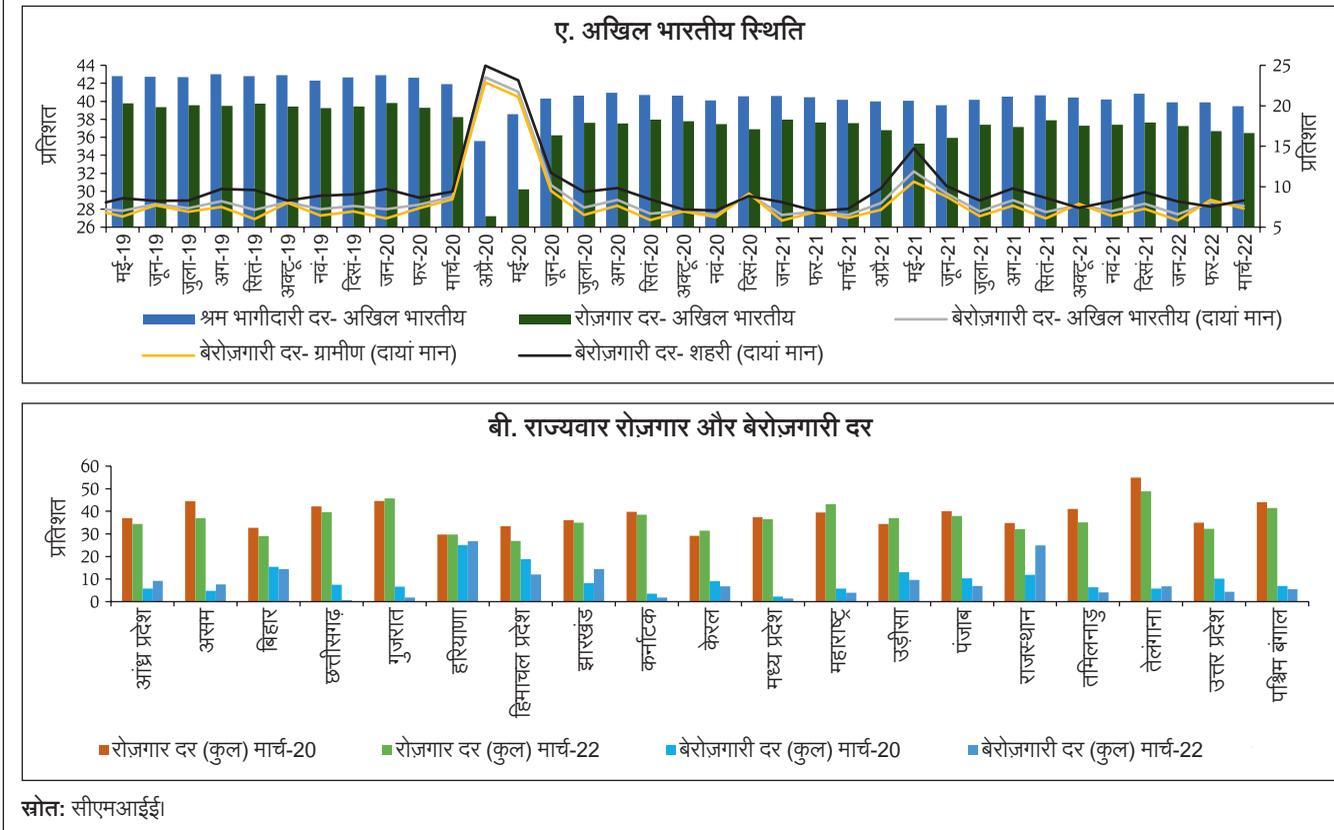
है और अपनी पूर्व-महामारी रोजगार दरों (चार्ट 13 बी) को पार कर लिया है।

सीएमआई के रोजगार आंकड़े बताते हैं कि नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या लगातार तीसरे महीने (चार्ट 14ए) में गिर गई। व्यवसाय की श्रेणी के अनुसार फरवरी से मार्च के बीच व्यवसायियों और वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई,

जबकि किसानों और छोटे व्यापारियों की संख्या में वृद्धि हुई। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) कई राज्यों में महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच गई है और कुछ में तो यह इससे भी आगे बढ़ गई है (चार्ट 14बी)।

पीएमआई बताते हैं कि मार्च में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि तीन महीने के संकुचन के बाद

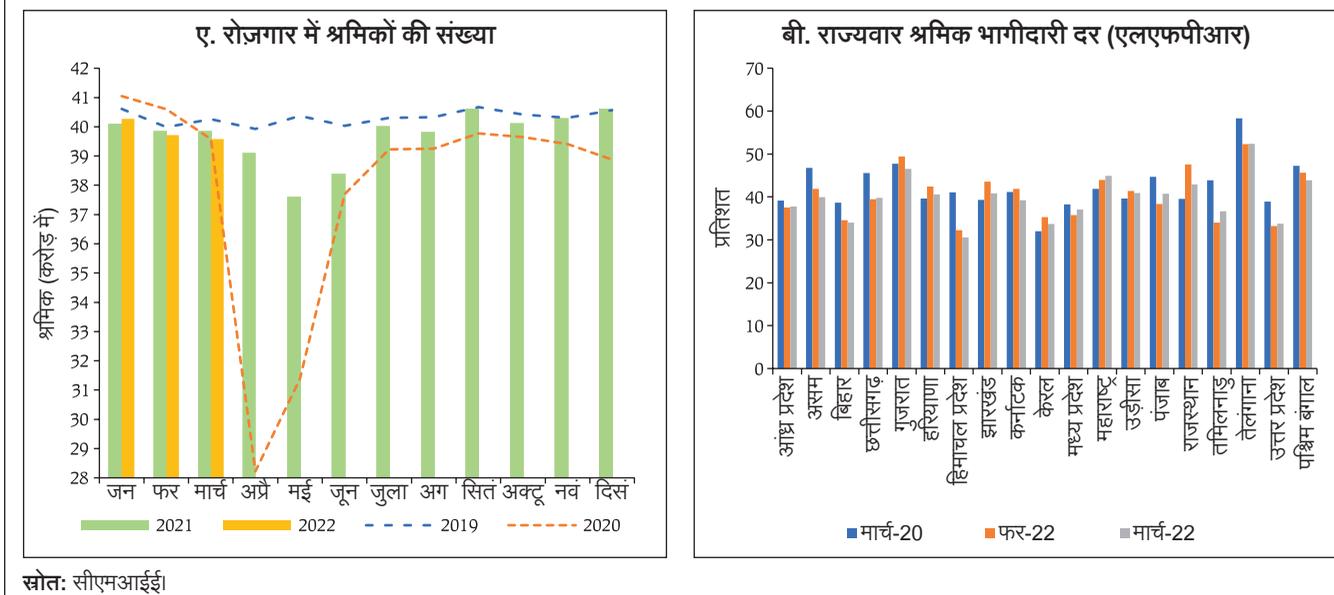
चार्ट 13: रोजगार, बेरोजगारी, और श्रम भागीदारी दरें

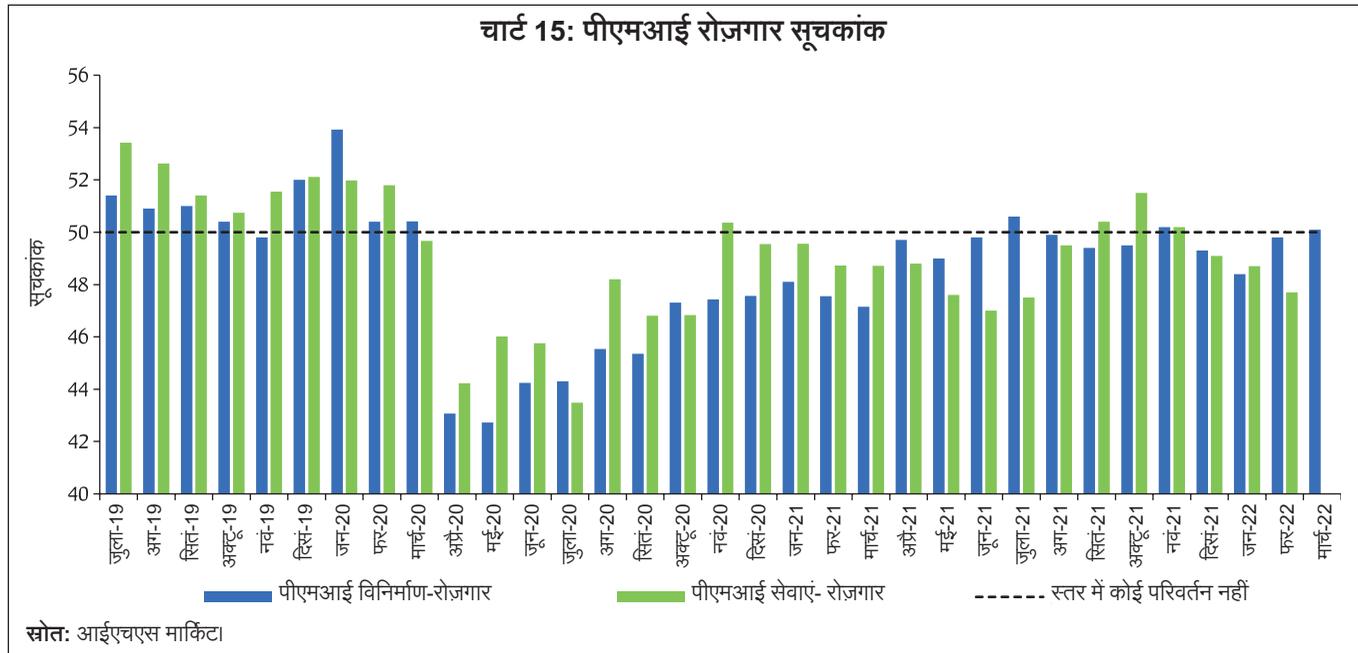


सूचकांक ने विस्तार में प्रवेश किया। सेवा क्षेत्र के रोजगार के लिए पीएमआई में लगातार चार महीनों की गिरावट के बाद भी सुधार हुआ (चार्ट 15)।

अप्रैल-सितंबर 2021 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के नवीनतम उपलब्ध परिणाम श्रम बाजार पर महामारी की दो लहरों

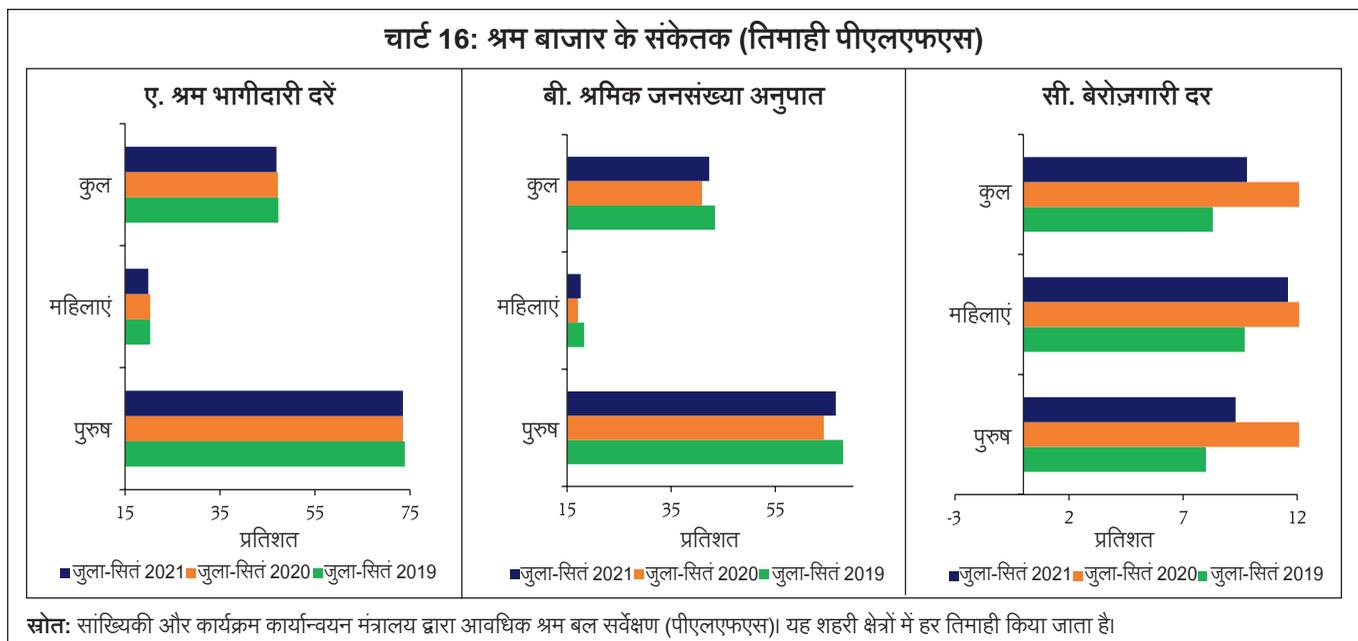
चार्ट 14: रोजगार में श्रमिकों की संख्या और एलएफपीआर



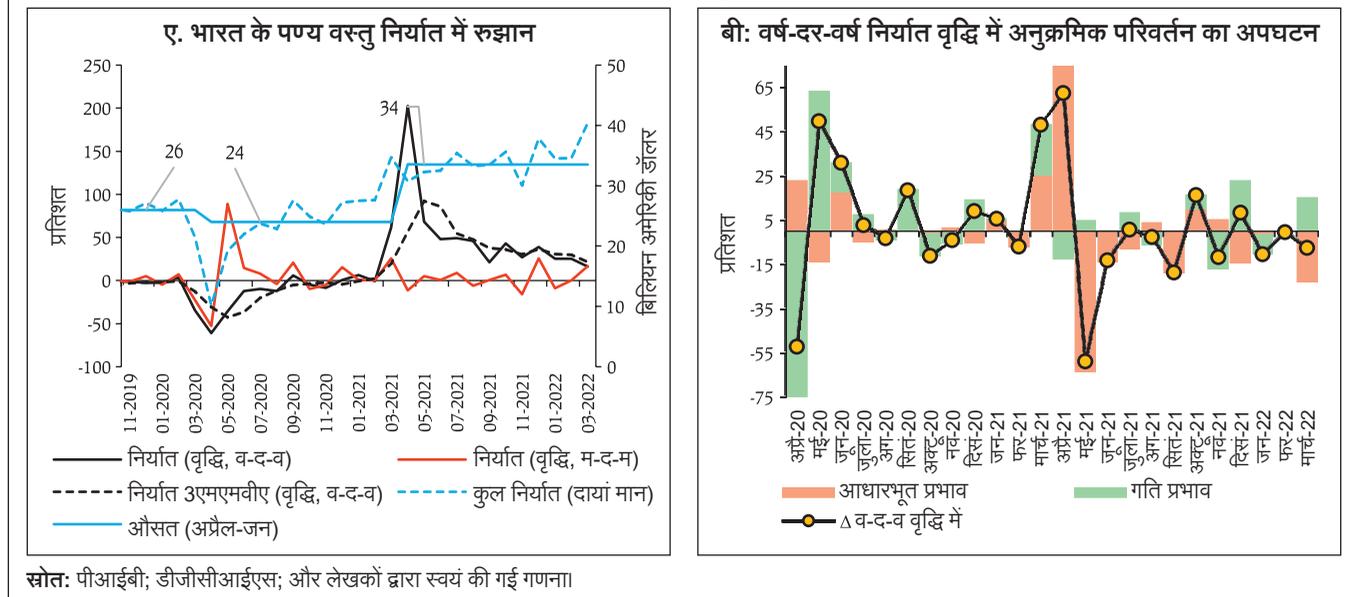


के प्रभाव कि पुष्टि करते हैं। 2019 और 2021 की जुलाई-सितंबर अवधि में श्रम भागीदारी दर (एलपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूआरआर) और बेरोजगारी दर (15 वर्ष और उससे अधिक की श्रेणी के लिए) जैसे प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों की तुलना से पता चलता है कि श्रम बाजार में अच्छा सुधार हुआ है लेकिन सुधार की गति धीमी है क्योंकि बेरोजगारी दर ऊंची बनी

हुई है। श्रम भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात उनके पूर्व-कोविड सितंबर 2019 के स्तर से मामूली पीछे है। यद्यपि सभी संकेतक महिला श्रम बल के लिए बदतर हैं, महामारी का प्रभाव लिंगों पर समान रूप से खराब रहा है (चार्ट 16)। महामारी ने दुनिया भर में श्रम बाजार और उद्योग की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। जैसा कि उद्योग 4.0⁵ गति प्राप्त कर रहा है, जीडीपी



चार्ट 17: भारत का पण्य वस्तु निर्यात - मार्च 2022

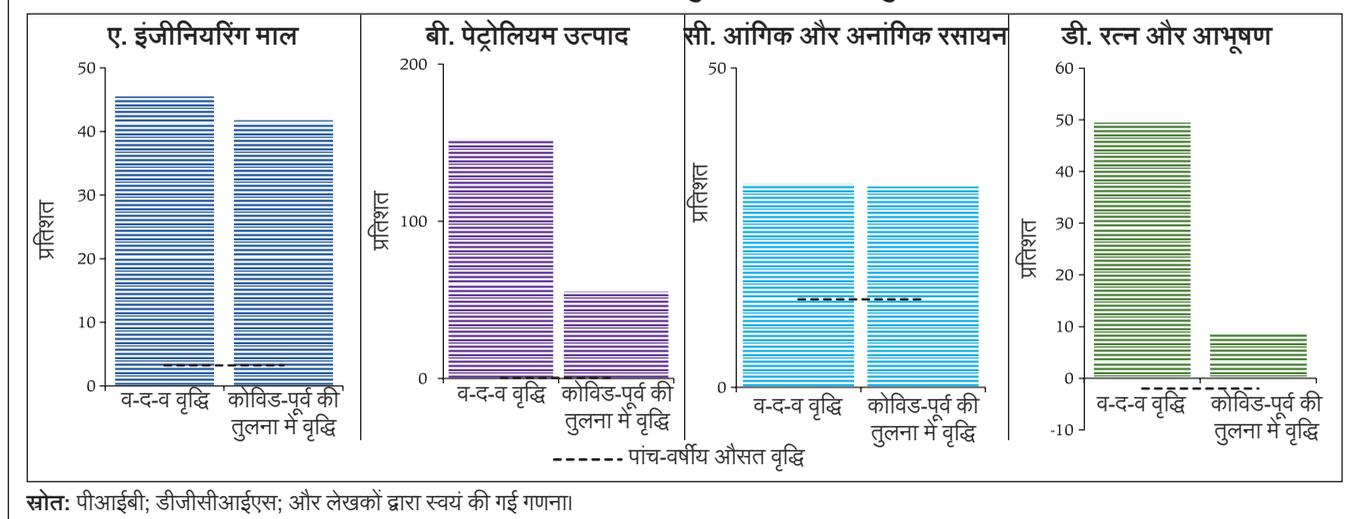


(अनुबंध) में उत्पादकता और श्रम हिस्सेदारी पर रोबोटिक्स के प्रभाव की फिर से जांच की जानी चाहिए।

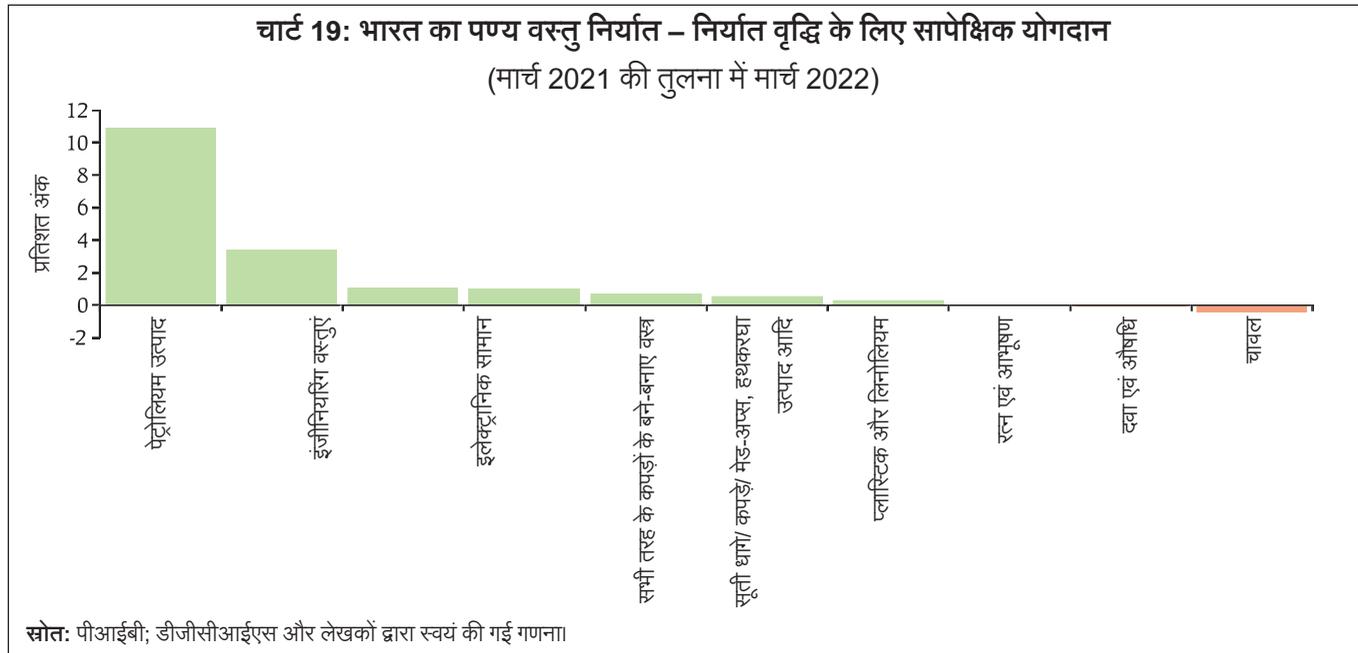
भारत का व्यापारिक निर्यात मार्च 2022 में 40.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मासिक ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के मुकाबले पूरे वर्ष के लिए 417.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया (चार्ट 17)। हाई-टेक सामान, भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों के निर्यात के लिए उत्पाद विविधीकरण

सहित कई पहल, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जैसे निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट ने मजबूत निर्यात प्रदर्शन में योगदान दिया है। प्रमुख वस्तुओं, जैसे, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन और रत्न और आभूषण के निर्यात में, जो निर्यात के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, 2021-22 (चार्ट 18) के दौरान मजबूत विस्तार देखा गया।

चार्ट 18: वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख निर्यातित वस्तुओं का विश्लेषण

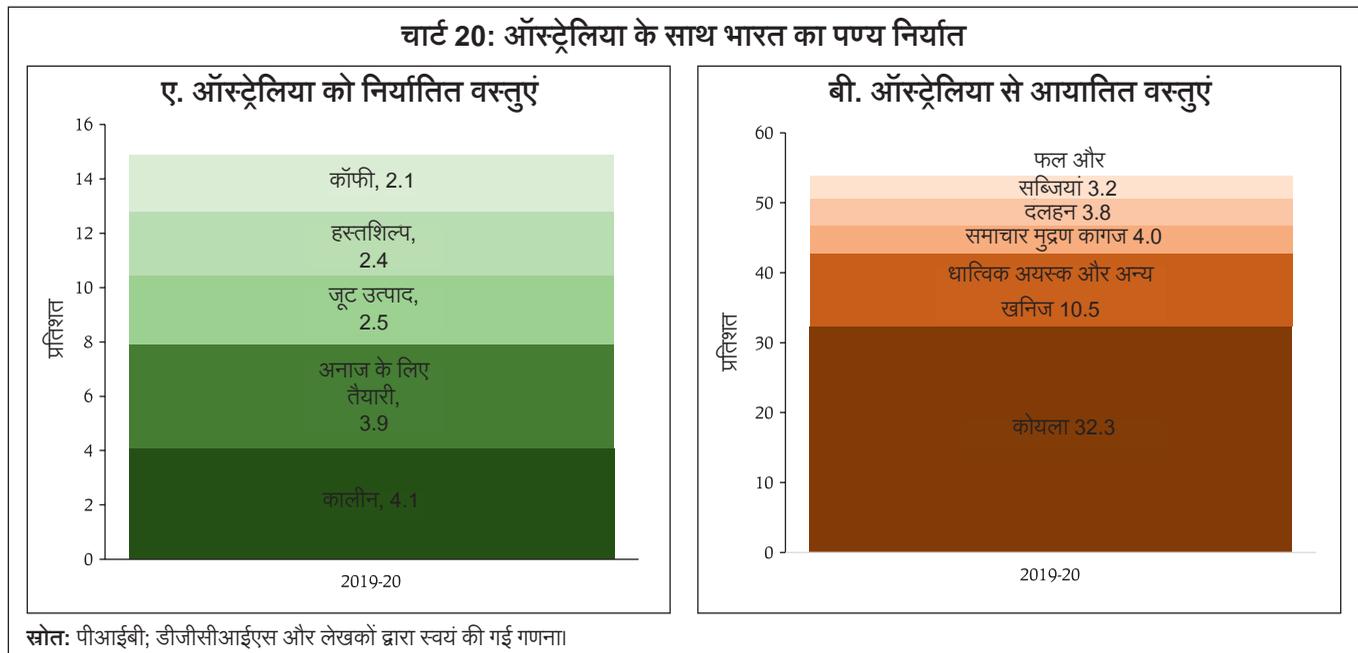


⁵ उद्योग 4.0 विनिर्माण के स्मार्ट तरीके को संदर्भित करता है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आदि की शक्ति का उपयोग करता है।



10 प्रमुख कमोडिटी समूहों में से 8, जिनका निर्यात 70 प्रतिशत से अधिक है, ने एक साल पहले की तुलना में विस्तार दर्ज किया। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं और रसायनों की बाहरी मांग ने निर्यात वृद्धि को बढ़ावा दिया (चार्ट 19)। 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इंजीनियरिंग सामान का निर्यात पहली बार 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जो ऑटोमोबाइल निर्यात के मजबूत शिपमेंट से सहायता प्राप्त है।

भारत ने 2 अप्रैल, 2022 को ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि अगले पांच वर्षों में 2021 में यूएस \$ 27.5 बिलियन से वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जा सके। ईसीटीए कपड़ा और परिधान, चमड़ा, और रत्न और आभूषण (चार्ट 20) में भारत की व्यापारिक निर्यात क्षमता को और मजबूत करने की उम्मीद है।

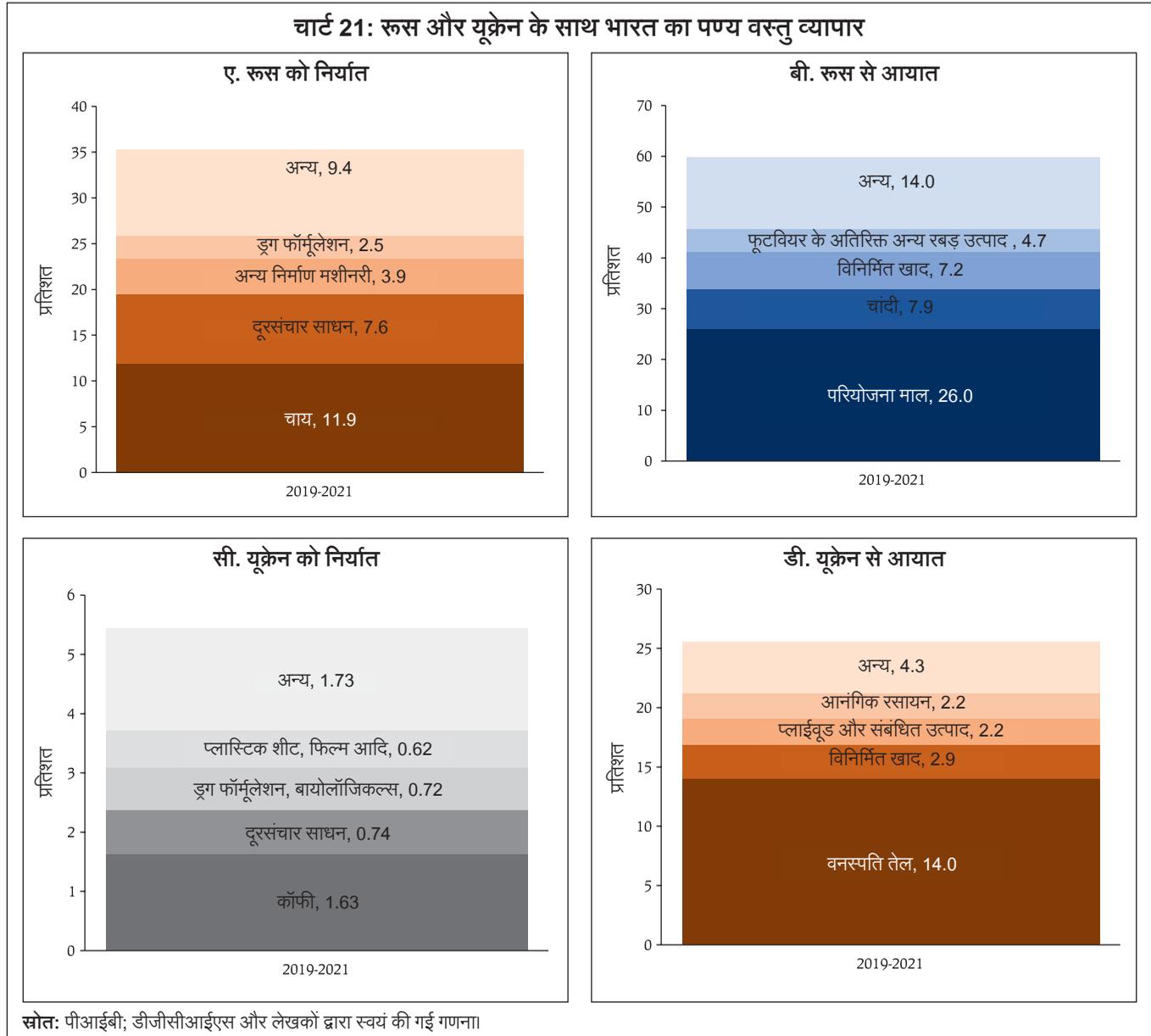


रूस और यूक्रेन के लिए भारत का प्रत्यक्ष व्यापार जोखिम सीमित है - रूस का भारत के व्यापारिक निर्यात और आयात में क्रमशः 0.9 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत का योगदान है, जबकि भारत के निर्यात और आयात में यूक्रेन का हिस्सा क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत के बराबर है। रूस और यूक्रेन के

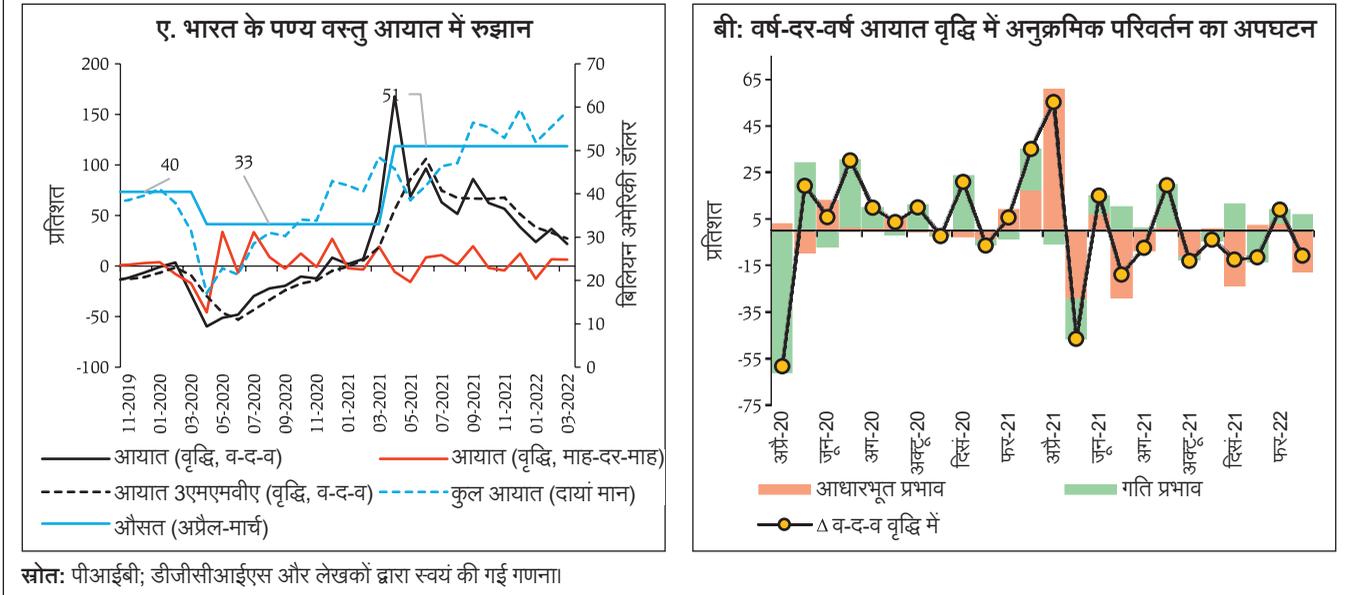
बाजारों में भारत का व्यापार जोखिम कुछ वस्तुओं (चार्ट 21) तक सीमित है।

मार्च 2022 में 59.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक वस्तुओं का आयात लगातार सातवें महीने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा और साल-दर-साल आधार पर 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 22)।

चार्ट 21: रूस और यूक्रेन के साथ भारत का पण्य वस्तु व्यापार

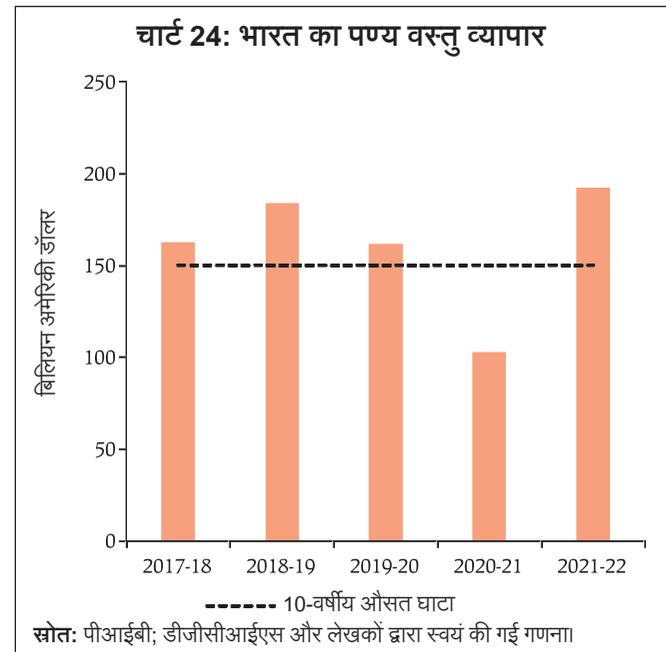
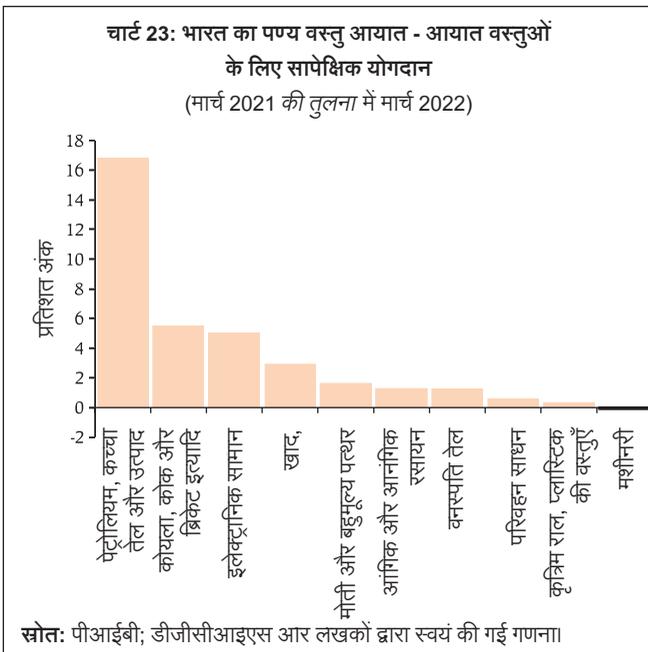


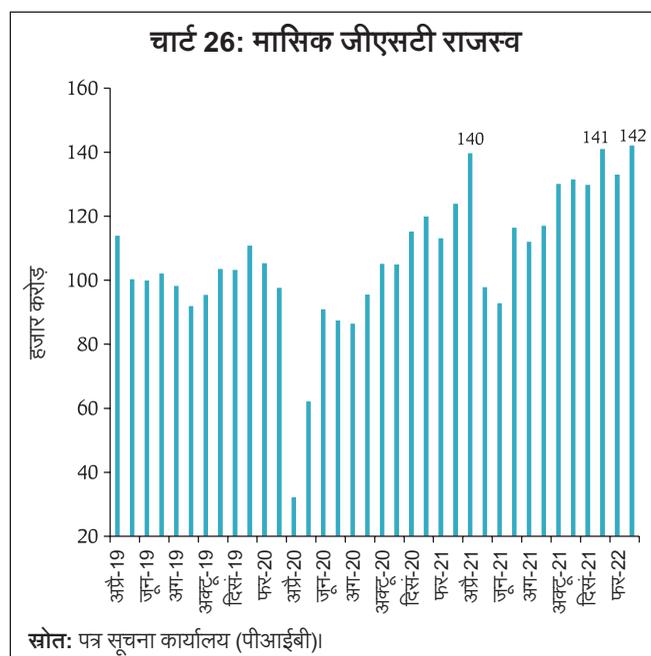
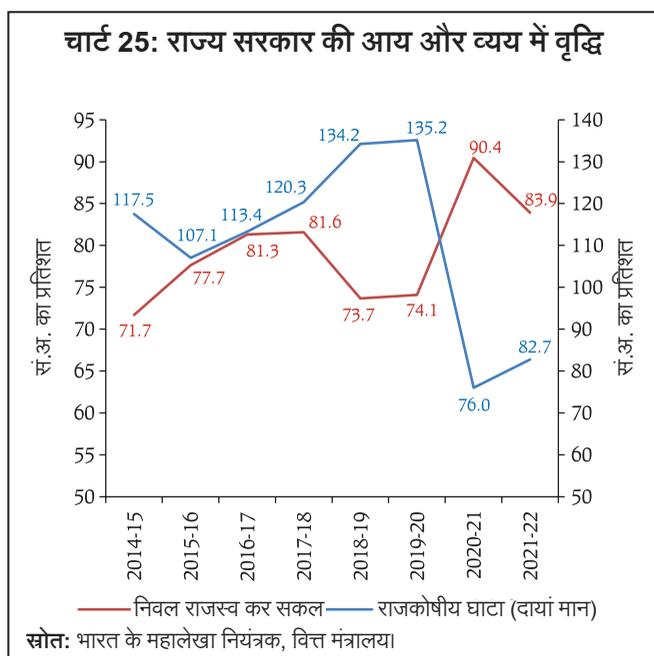
चार्ट 22: भारत का पण्य वस्तु आयात - मार्च 2022



कोयले और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की उच्च मांग से प्रेरित थी (चार्ट 23)। एक साल पहले की तुलना में मार्च में तेल का आयात लगभग दोगुना हो गया, जो कच्चे तेल की कीमतों में सालाना 74.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। सोने की कीमतों में क्रमिक वृद्धि के कारण मार्च 2022 में सोने के आयात में 8 महीने का न्यूनतम मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।

भारत का व्यापार घाटा मार्च 2022 में बढ़कर 18.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मार्च 2021 में 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था; हालांकि, इसमें क्रमिक आधार पर नरमी आई। वार्षिक आधार पर, वाणिज्यिक व्यापार घाटा 2021-22 के दौरान एक साल पहले के 102.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (चार्ट 24) के मुकाबले अब तक के उच्चतम स्तर 192.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।





अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में पिछले वर्षों की प्रवृत्ति (चार्ट 25) की तुलना में सुधार हुआ है। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व 2021-22 में बजट अनुमान से 4.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान कुल व्यय में 2020-21 की तुलना में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में क्रमशः 19.7 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-फरवरी के दौरान, पूंजीगत परिव्यय (ऋण और अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में सालाना 61.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आरई को पूरा करने के लिए, हालांकि, मार्च 2022 में पूंजीगत व्यय को सालाना 458.4 प्रतिशत बढ़ने की आवश्यकता होगी।

मार्च 2022 में, जीएसटी संग्रह ने ₹1.42 लाख करोड़ का सर्वकालिक उच्चता दर्ज की, जो जनवरी 2022 में प्राप्त ₹1.41 लाख करोड़ के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया। इसके साथ, 2021-22 में औसत मासिक संग्रह ₹1.24 लाख करोड़ है और ति4:2021-22 में औसत मासिक संग्रह ₹1.39 लाख करोड़ (चार्ट 26) है।

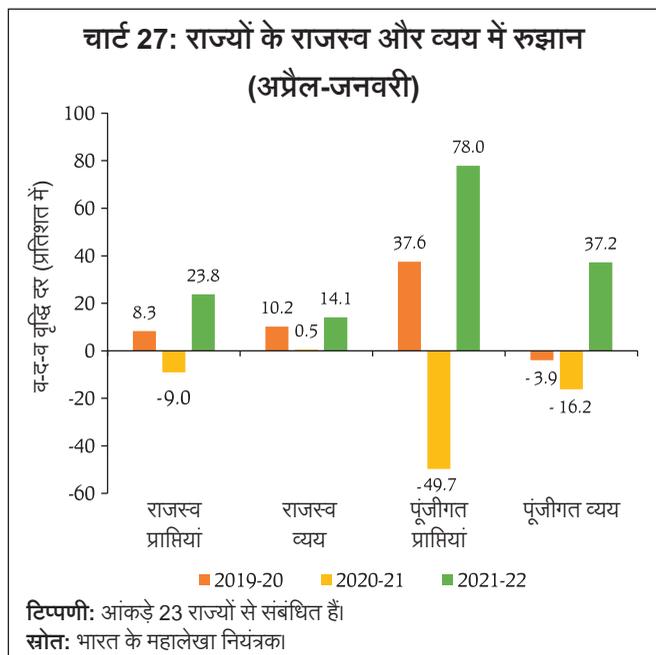
राज्यों की राजस्व प्राप्तियों ने अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान 23.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जबकि एक साल

पहले इसमें 9 प्रतिशत की गिरावट आई थी, और जनवरी 2020 के अपने पूर्व-महामारी के स्तर से आगे निकल गए हैं। कर (जीएसटी, बिक्री कर, और संघ के सकल करों में राज्यों की हिस्सेदारी सहित) और राज्यों के स्वयं के गैर-कर राजस्व दोनों में मजबूत वृद्धि से यह परिलक्षित हुआ था⁶ अप्रैल-जनवरी 2021-22 में केंद्र से राज्यों को सहायता अनुदान और योगदान में 8.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसी तरह, राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियों ने इसी अवधि के दौरान तेज वृद्धि दर्ज की, लेकिन उनके पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रही।

अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान राज्यों का राजस्व व्यय एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 14.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा। अचानक गिरावट (एक साल पहले) के बाद अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान राज्यों के पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि, पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के संयोजन के साथ राजकोषीय गुणक के व्यापक प्रभावों के माध्यम से दीर्घकालिक विकास के लिए शुभ संकेत है (चार्ट 27)।

⁶ स्वयं के गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

गैर-कर राजस्व राज्य के अपने गैर-कर राजस्व और केंद्र से अनुदान और सहायता-योगदान का योग है।



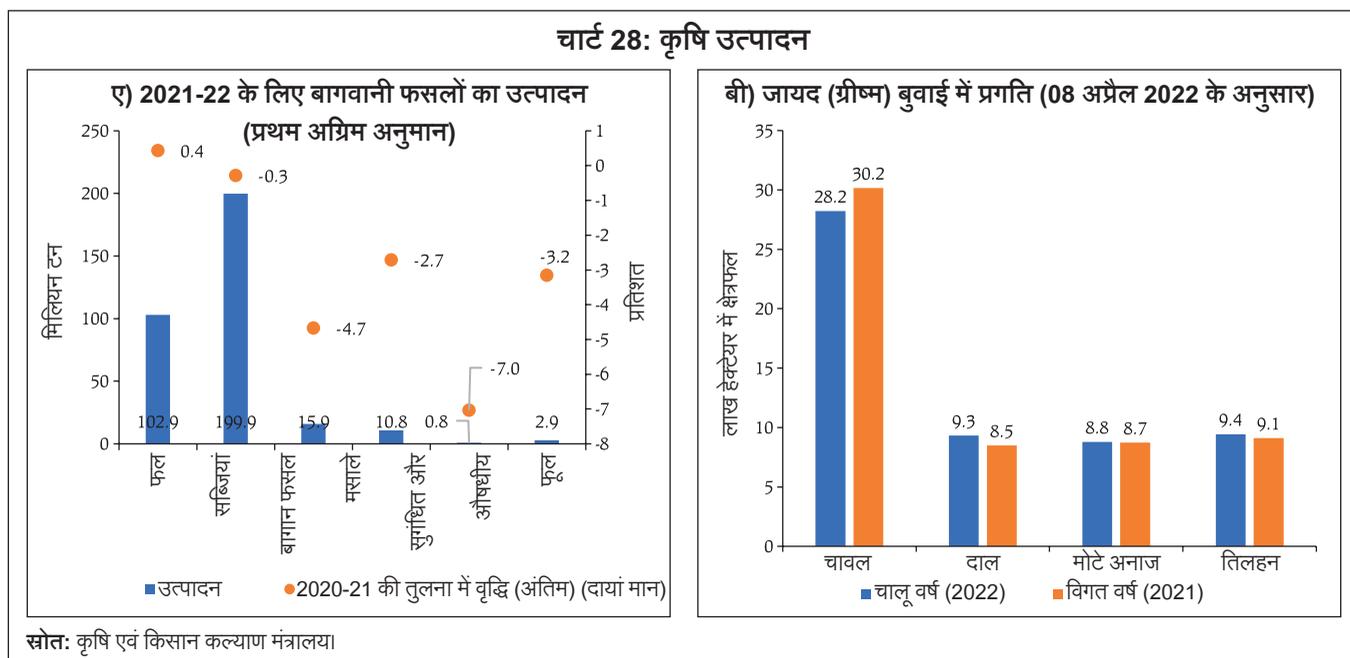
राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में तेज वृद्धि, राजस्व व्यय में मामूली वृद्धि के साथ, अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सकल राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे दोनों में क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 45.4 प्रतिशत की गिरावट आई। यह उल्लेखनीय है कि राज्य इस वर्ष अब तक अपने बजटीय सकल राजकोषीय घाटे से 33.3 प्रतिशत कम हैं,

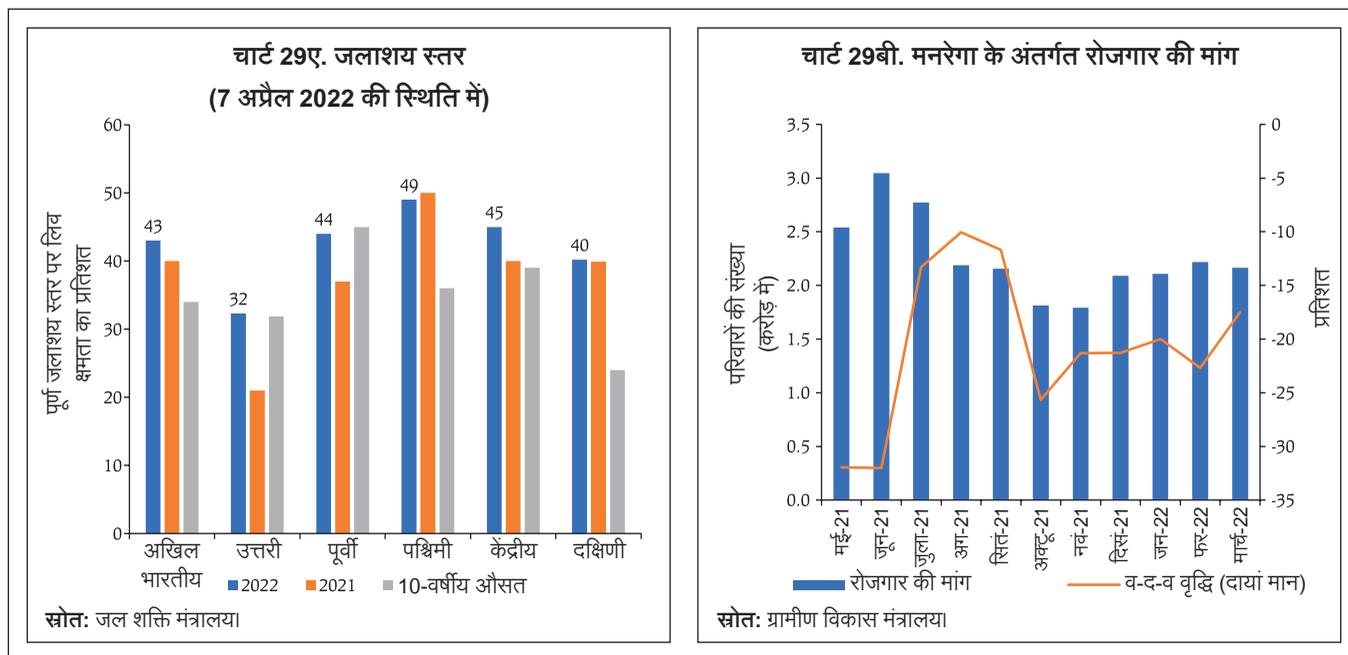
जिससे वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान व्यय में और वृद्धि गुंजाइश है।

कुल आपूर्ति

28 मार्च, 2022 को जारी पहले अग्रिम अनुमानों (ईई) के अनुसार बागवानी उत्पादन 333.3 मिलियन टन से अधिक आंका गया था, जो पहले ईई की तुलना में 2.0 प्रतिशत अधिक है और 2020-21 के अंतिम अनुमानों से मामूली कम है (चार्ट 28 ए) सब्जियों का उत्पादन - आलू (-4.6 प्रतिशत); और टमाटर (-4.2 प्रतिशत) - में गिरावट आई, जबकि रकबे में वृद्धि (17.9 प्रतिशत) के कारण प्याज उत्पादन में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फलों का उत्पादन भी 2020-21 में मामूली रूप से बढ़ा।

मार्च से मई तक रबी और खरीफ के बीच गर्मी या जायद का मौसम एक छोटी मध्य अवधि है। 08 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल गर्मियों में बोई गई फसल का रकबा 55.8 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो एक साल पहले की तुलना में 1.3 प्रतिशत कम है, जिसका मुख्य कारण चावल का रकबा कम होना है (चार्ट 28बी)। 07 अप्रैल 2022 तक 140 प्रमुख जलाशयों में कुल संग्रहण, पिछले वर्ष के दौरान एफआरएल के 40 प्रतिशत की तुलना में पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) के 43 प्रतिशत से





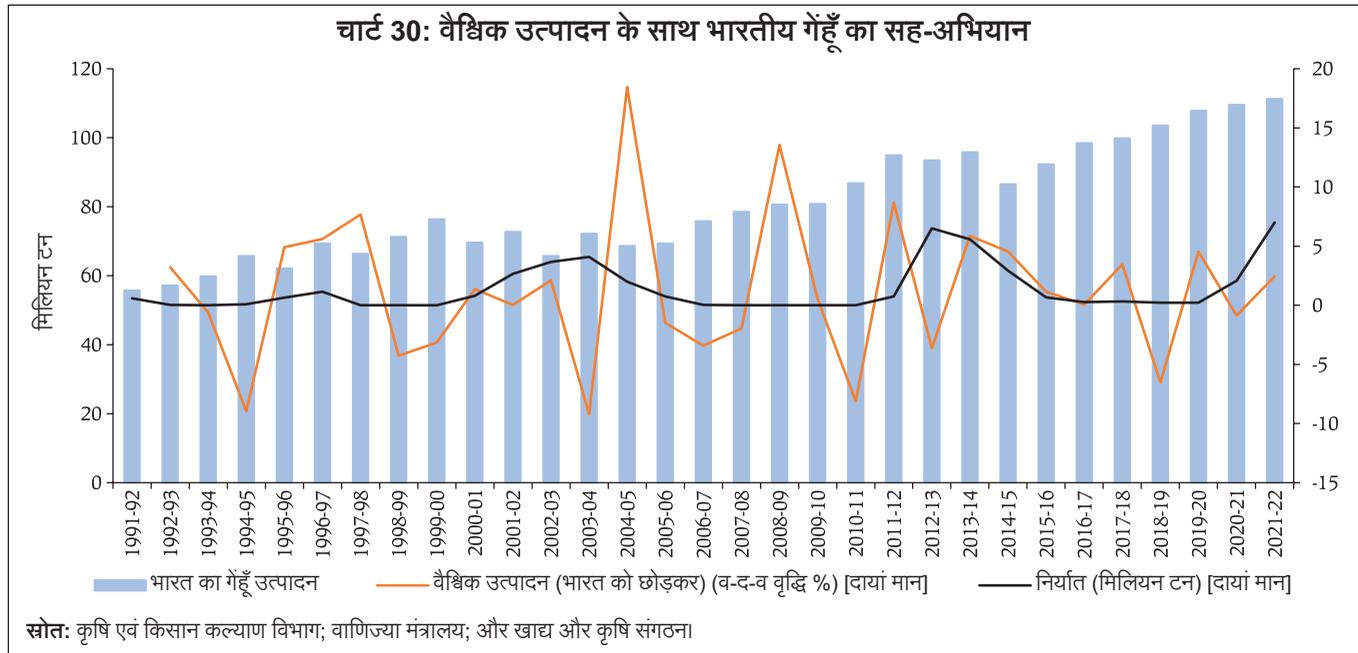
अधिक था। जल का वर्तमान स्तर एफआरएल (चार्ट 29ए) के पिछले 10 वर्षों के औसत 34 प्रतिशत से अधिक है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार की मांग एक साल पहले के स्तर की तुलना में कम बनी हुई है, जो कि कम कृषि मौसम के बावजूद गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के उच्च अवसरों का संकेत देती है।

12 अप्रैल 2022 तक, चालू खरीद विपणन सत्र के दौरान चावल की कुल खरीद संघयी रूप से 50.6 मिलियन टन तक पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यह 47.1 मिलियन टन थी। इस पूरे सीजन में चावल खरीद का लक्ष्य 52.8 मिलियन टन रखा गया है। गेहूं की रिकॉर्ड कटाई के साथ, कुछ राज्यों में रबी विपणन सत्र के तहत गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है, जिसमें इस सीजन के लिए 44 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण (5 किग्रा / माह) ₹ 80,000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय के साथ छह महीने (अप्रैल से सितंबर) के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पहल के लिए सुविधाजनक स्टॉक स्तर (क्रमशः चावल और गेहूं के लिए बफर मानदंडों का 7.2 और 1.4 गुना)

अच्छा संकेत देगा। मौजूदा भू-राजनीतिक संकट को देखते हुए वैश्विक गेहूं की आपूर्ति कम हो गई है। रूस और यूक्रेन से अनुमानित निर्यात, जो 2020-21 में वैश्विक गेहूं निर्यात का 28 प्रतिशत था, को काफी कम कर दिया गया है। यह, बदले में, दुनिया के बाकी हिस्सों में व्यापार पुनर्वितरण और मांग नियंत्रण को गति प्रदान कर सकता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ, पर्याप्त और प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले व्यापार योग्य अधिशेष के साथ वैश्विक मांग अंतर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में उत्पादित गेहूं की समान किस्म और मार्च और अप्रैल तक रिकॉर्ड फसल पूरी होने के साथ, भारत से इस साल रिकॉर्ड 10 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने की उम्मीद है (चार्ट 30)।

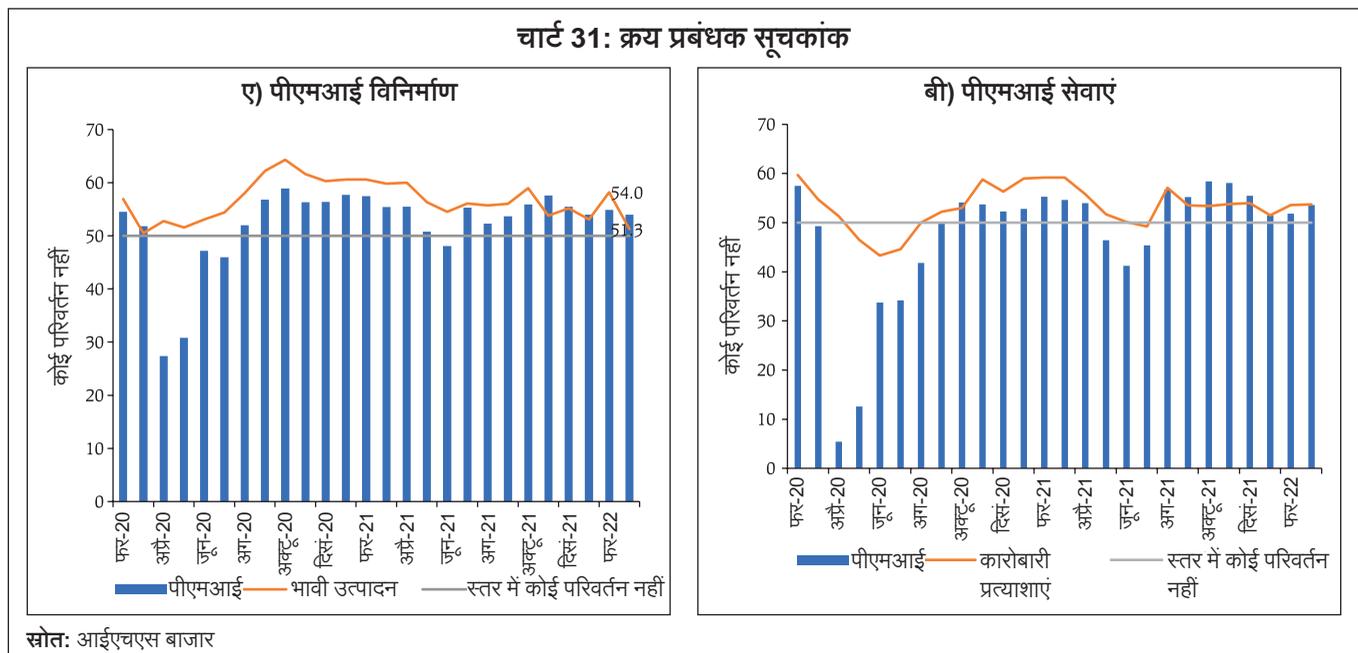
औद्योगिक क्षेत्र में, पीएमआई का हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई विस्तार पहली बार मार्च 2022 में फरवरी में 54.9 से घटकर 54.0 हो गया, क्योंकि कंपनियों ने नए ऑर्डर और उत्पादन में नरम विस्तार की सूचना दी थी। भू-राजनीतिक जोखिमों (चार्ट 31ए) के कारण आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स अपने लंबे समय के औसत से दो साल के निचले स्तर तक गिर गया।



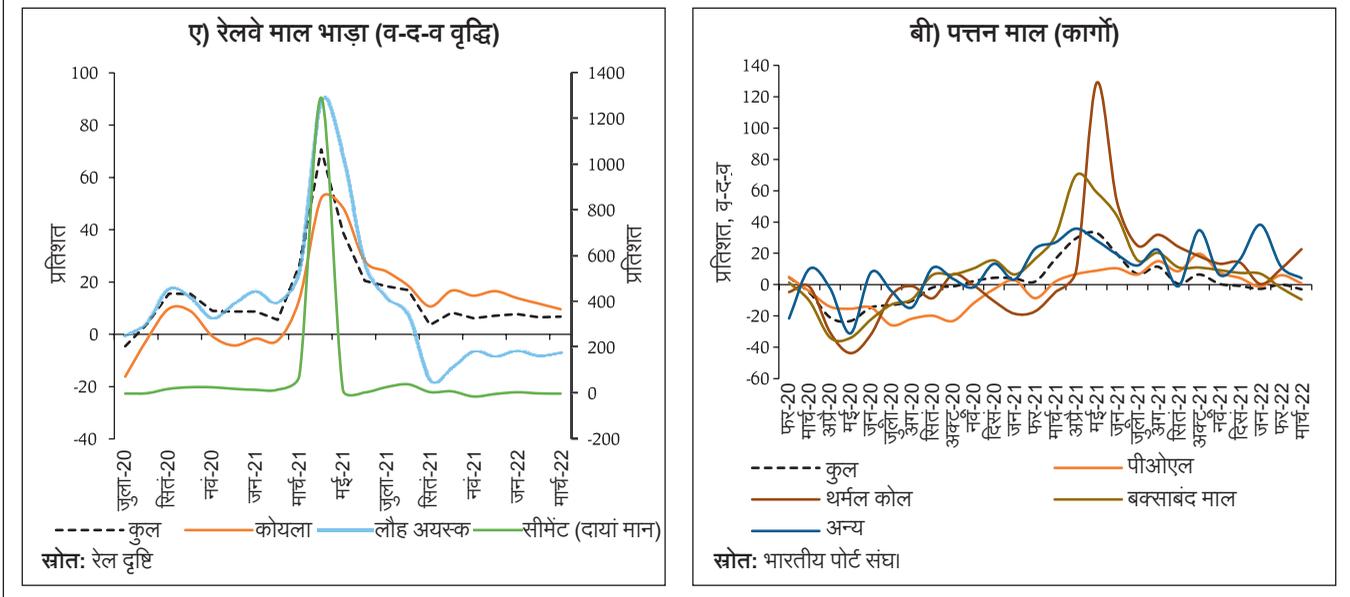
पीएमआई सेवाएं मार्च में एक महीने पहले के 51.8 से बढ़कर 53.6 हो गईं, जो दिसंबर 2021 के बाद से विस्तार की सबसे मजबूत दर दर्ज कर रही है और लगातार आठवें महीने तक विस्तार की दौड़ को बढ़ा रही है। व्यापार प्रत्याशा सूचकांक (भविष्य गतिविधि सूचकांक) में भी फरवरी 2022 की तुलना में मामूली सुधार हुआ (चार्ट 31 बी)। सेवा क्षेत्र में, परिवहन संकेतकों

ने विस्तार दर्ज किया, पिछले साल दर्ज किए गए उच्च आधार के बावजूद, मार्च में रेलवे माल ढुलाई में 6.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट 32 ए)।

एक साल पहले उच्च आधार पर लौह-अयस्क और सीमेंट में गिरावट के बावजूद कोयले में माल ढुलाई में वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो में बढ़ोतरी दर्ज की गई,



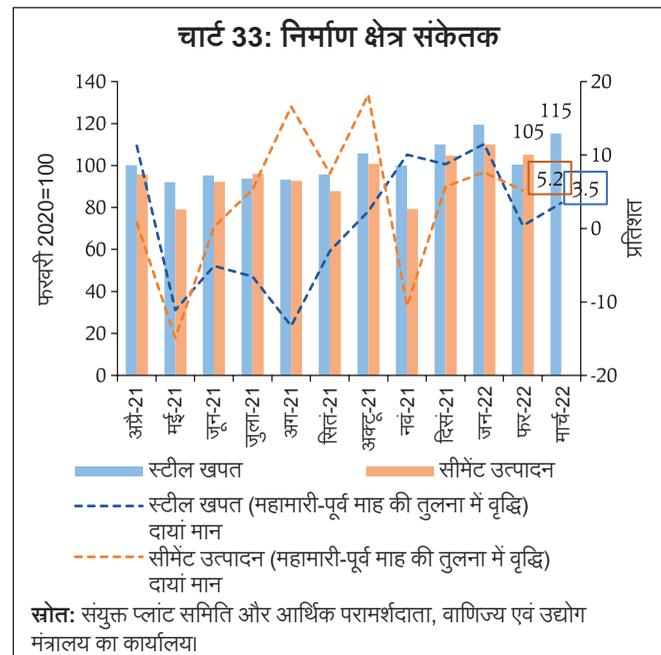
चार्ट 32: रेलवे और कार्गो ट्रैफिक



जिसमें सभी प्रमुख वस्तुओं के लिए कार्गो पूर्व-महामारी के आंकड़ों से उपर या तुलनीय था। व-द-व आधार पर इसने उच्च आधार पर संकुचन दर्ज किया। 2021-22 में, कार्गो में एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान, कार्गो ने 1.1 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की (चार्ट 32बी)।

रही। भारत सरकार ने 27 मार्च से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, जो आगामी महीनों में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है (सारणी 1)।

फरवरी-मार्च 2022 के दौरान निर्माण क्षेत्र में गतिविधि में तेजी आई, जिसमें सीमेंट उत्पादन और इस्पात की खपत में पूर्व-महामारी के स्तर में विस्तार दर्ज किया गया (चार्ट 33)। अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधि से प्रेरित मांग द्वारा समर्थित कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद निरंतर सुधार आता है।



मार्च 2022 में भारतीय विमानन क्षेत्र में सुधार जारी रहा। दैनिक घरेलू हवाईअड्डे का औसत प्रति दिन औसतन 6.8 लाख रहा जिसमें पिछले महीने की तुलना में 25.5 प्रतिशत का विस्तार देखा गया। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या में भी क्रमिक रूप से 25.1 प्रतिशत का सुधार हुआ, जबकि कार्गो खंड में, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो में क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल के पहले दस दिनों में घरेलू हवाईअड्डों पर आने वालों की संख्या मार्च की इसी अवधि की तुलना में स्थिर

सारणी 1: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

क्षेत्र	संकेतक	उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाओं की वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)							2019 की तुलना में वृद्धि				
		सितं-21	अक्तू-21	नवं-21	दिसं-21	जन-22	फर-22	मार्च-22	नवं 21/ नवं 19	दिसं 21/ दिसं 19	जन 22/ जन 20	फर 22/ फर 20	मार्च 22/ मार्च 19
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	-41.2	-27.1	-18.6	-13.3	-8.1	-6.5		-14.8	-1.5	2.2	10.2	
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	-17.4	-24.9	-34.4	-10.8	-21.1	-27.3		-25.5	-4.2	-15.9	-19.8	
	तीन पहिया वाहन बिक्री	53.8	19.1	-6.6	27.0	-8.5	-1.1		-59.7	-47.7	-60.4	-34.5	
	ट्रैक्टर बिक्री	-14.8	0.4	-22.5	-27.5	-32.6	-31.3	-14.3	17.2	3.8	-1.2	-10.0	17
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	24.5		0.9						-0.3			
	रेलवे माल दुलाई यातायात	3.6	8.4	6.1	7.2	7.7	6.6	6.7	15.6	16.5	17.1	12.4	16.3
	पोर्ट कार्गो यातायात	0.5	6.3	-0.2	-0.4	-2.9	-2.7		3.9	4.0	1.0	2.0	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	10.1	6.7	-1.7	2.0	-6.1	-6.3		-11.4	-1.1	-14.8	-12.5	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	18.1	23.8	11.7	10.5	5.2	-0.4		-5.0	-3.6	-7.6	-10.2	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	76.5	68.7	65.5	53.3	-16.2	-1.0		-17.6	-12.5	-48.6	-36.6	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	155.9	162.9	140.2	121.7	67.5	66.6		-58.6	-54.5	-61.3	-56.0	
	जीएसटी ई-वे बिल्लस (कुल)	18.3	14.5	5.9	11.6	9.5	8.3	9.7	14.5	29.3	20.9	20.9	42.4
	जीएसटी ई-वे बिल्लस (आंतर राज्य)	15.6	14.1	7.3	13.4	11.4	10.3	11.8	17.6	33.0	25.9	26.3	49
	जीएसटी ई-वे बिल्लस (अंतर राज्य)	22.3	15.1	3.9	8.9	6.6	5.3	6.6	10.1	24.0	13.8	13.3	33
यात्री आगमन	278.8	337.0	255.0	235.5	140.4			-76.9	-75.2	-82.0			
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	-3.2	-3.8	-7.1	-8.3	0.5	-10.6	1.4	10.1	8.7	11.5	0.4	3.5
	सीमेंट उत्पादन	11.3	14.5	-3.6	13.9	14.3	5.0		-10.6	5.7	7.6	5.2	
पीएमआई संकेतक	विनिर्माण	53.7	55.9	57.6	55.5	54.0	54.9	54.0					
	सेवाएँ	55.2	58.4	58.1	55.5	51.5	51.8	53.6					

स्रोत: सीएमआई, सीआईसी आंकड़े; आईएचएस बाजार; एसआईएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त प्लान्ट समिति।

मुद्रास्फीति

एनएसओ द्वारा 12 अप्रैल, 2022 को जारी किए गए मार्च 2022 के अनंतिम सीपीआई डेटा से पता चलता है कि मार्च में लगभग 100 बीपीएस की सकारात्मक मूल्य गति (महीने-दर-महीने कीमतों में बदलाव) 10 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभावों से समायोजन (एक वर्ष पहले के माह-दर-माह कीमतों में बदलाव) के परिणामस्वरूप फरवरी और मार्च के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में करीब 90 बीपीएस यानी 6.1 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। (चार्ट 34 ए)।

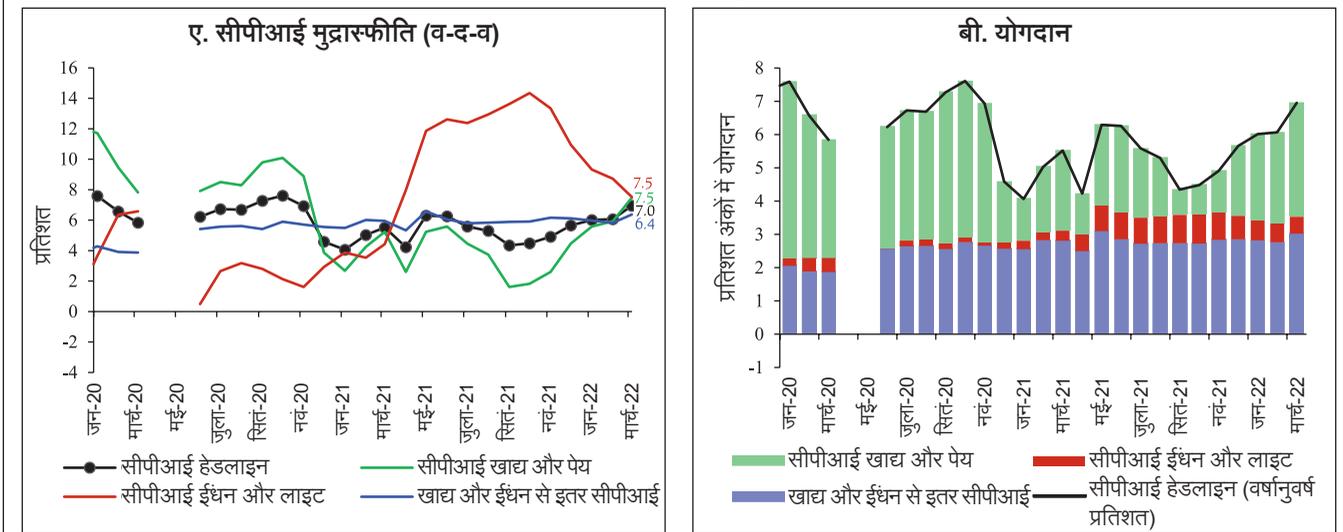
खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति मुख्य चालक थी, जो फरवरी में 5.9 प्रतिशत थी मार्च में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों के संदर्भ में, अनाज, मांस और मछली, दूध, खाद्य तेल, फल, सब्जियां, चीनी, मसाले और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। दूसरी ओर, अंडे, दाल और गैर-मादक पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति में नरमी आई।

सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति लगातार पांचवें महीने मुख्य रूप से एलपीजी मुद्रास्फीति में कमी के कारण नरम हुई – जो फरवरी के 8.7 प्रतिशत से मार्च में 7.5 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, केरोसिन (पीडीएस) मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि जारी रही। मार्च में बिजली की कीमतें अवस्फीति में रहीं। सीपीआई ईंधन (सीपीआई बास्केट में 6.84 प्रतिशत का भार) ने फरवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 7.3 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 34बी)।

खाद्य और ईंधन⁷ या कोर मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च में 50 बीपीएस बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 5.8 प्रतिशत थी (चार्ट 34ए)। यह वृद्धि मुख्य रूप से व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, कपड़े और जूते, घरेलू सामान और सेवाओं, स्वास्थ्य खेलकूद और मनोरंजन से उत्पन्न दबावों के कारण हुई थी।

⁷ सीपीआई शीर्षक से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाकर खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई पर काम किया जाता है।

चार्ट 34: सीपीआई मुद्रास्फीति

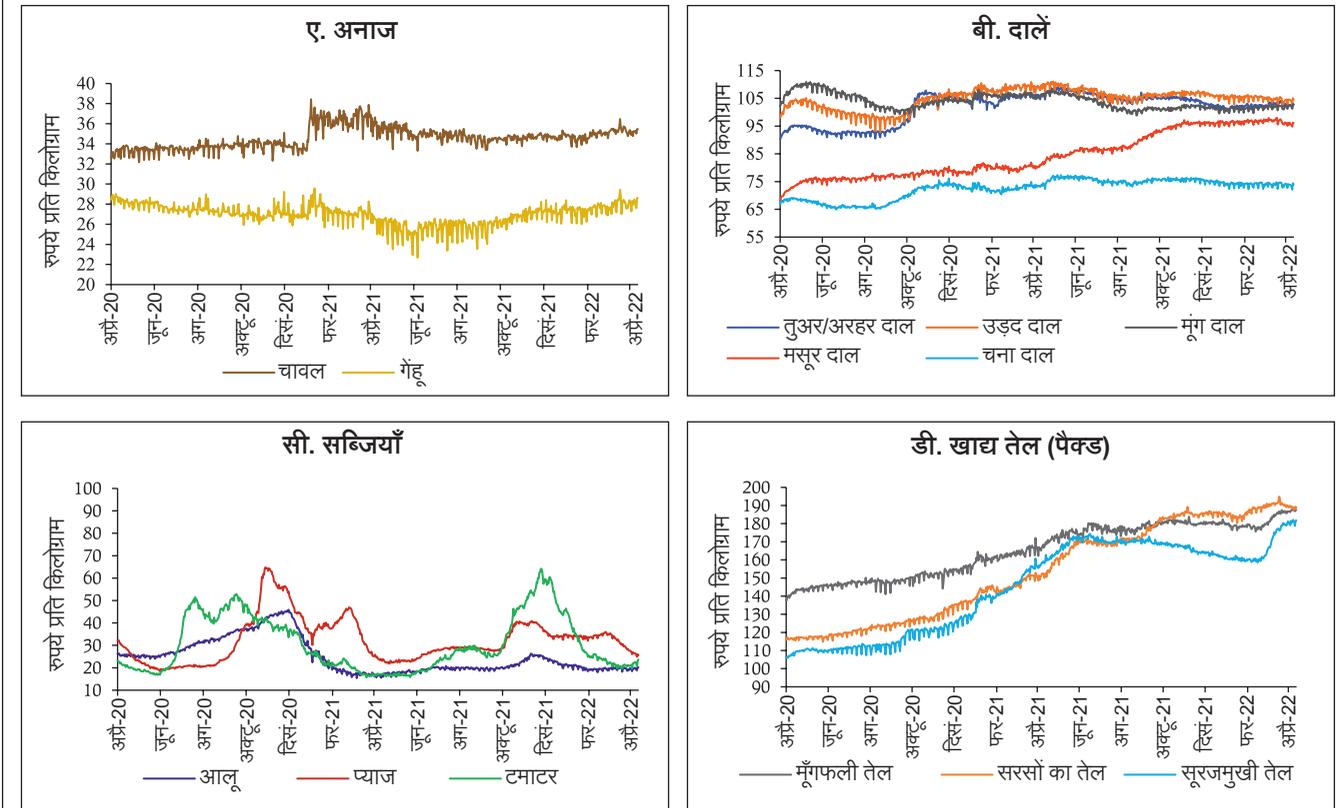


टिप्पणी: अप्रैल- मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल- मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान

आवास, परिवहन एवं संचार और शिक्षा उप-समूहों में मुद्रास्फीति में नरमी आई।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों के विभाग) के अब तक के अप्रैल (1-12 अप्रैल,

चार्ट 35: डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य



स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ अनुमान

2022) के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा चावल की कीमतों में कुछ कमी का संकेत देते हैं, भले ही गेहूं की कीमतें बढ़ रही हों। मूंग को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य तेलों के मामले में, सोया, सूरजमुखी और मूंगफली तेल जैसे रिफाइंड तेलों में कीमतों का दबाव बना रहा, जबकि सरसों के तेल की कीमतों में गिरावट आई। सब्जियों में आलू और प्याज की कीमतों में गिरावट देखी गई, जबकि टमाटर की कीमतों में अप्रैल से अब तक में वृद्धि हुई है (चार्ट 35)।

22 मार्च 2022 से पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। 12 अप्रैल 2022 तक पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतों में लगभग ₹10 प्रति लीटर की संचयी वृद्धि दर्ज की गई और यह क्रमशः ₹112.97 प्रति लीटर (चार प्रमुख महानगरों में पंप की कीमतों का औसत) और ₹100.55 प्रति लीटर रही। 6 अक्टूबर, 2021 के बाद पहली बार 22 मार्च 2022 को रसोई गैस की कीमतों में ₹50 प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई। मार्च में बढ़ने के बाद अप्रैल की शुरुआत में मिट्टी के तेल की कीमतें स्थिर रहीं (सारणी 2)।

पीएमआई में परिलक्षित विनिर्माण और सेवाओं में मार्च में निविष्टि लागत में और वृद्धि हुई। जबकि बिक्री की कीमतें पूरे विनिर्माण क्षेत्र में पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, वे सेवाओं में केवल मामूली रूप से बढ़ीं।

सारणी 2: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			महीने दर महीने (प्रतिशत)	
		अप्रै-21	मार्च-22	अप्रै-22 ^	मार्च-22	अप्रै-22
पेट्रोल	₹/लीटर	92.64	103.98	112.06	1.1	7.8
डीजल	₹/लीटर	84.54	91.62	99.65	1.2	8.8
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	30.32	46.87	46.87	11.3	0.0
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	819.63	926.25	960.13	1.8	3.7

^: 1-12 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान

IV. वित्तीय स्थितियां

एमपीसी के 8 अप्रैल, 2022 के प्रस्ताव में मौद्रिक नीति के रुख के पुनर्मूल्यांकन के अनुरूप, रिजर्व बैंक ने अपनी परिचालन प्रक्रिया में भी बदलाव किए, जो उसी दिन के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के बयान से लिए गए हैं ताकि प्रमुख निहितार्थ निकाला जा सके:

- “2018 में आरबीआई अधिनियम की धारा 17 में संशोधन ने रिजर्व बैंक को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) शुरू करने का अधिकार दिया। केंद्रीय बैंक पर बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को हटाकर, एसडीएफ मौद्रिक नीति के परिचालन फ्रेमवर्क को मजबूत करता है। तदनुसार, अब एसडीएफ को एलएएफ कॉरिडोर के आधार के रूप में पेश करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉरिडोर के ऊपरी छोर पर स्थायी अंतर्वेशन साधन अर्थात् सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के समान, एलएएफ कॉरिडोर के निचले भाग में एक स्थायी अवशोषण सुविधा शुरू करके मौद्रिक नीति के परिचालन फ्रेमवर्क को समरूपता प्रदान करेगा। इस प्रकार, एलएएफ कॉरिडोर के दोनों सिरों पर स्थायी सुविधाएं होंगी - एक अवशोषित करने के लिए और दूसरी चलनिधि अंतर्वेशन के लिए। तदनुसार, एसडीएफ और एमएसएफ तक पहुंच बैंकों के विवेक पर होगी, रिपो/रिवर्स रिपो, ओएमओ और सीआरआर के विपरीत, जो रिजर्व बैंक के विवेक पर उपलब्ध हैं। विशेष रूप से, चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता साधन भी है।
- एसडीएफ दर नीतिगत दर से 25 बीपीएस कम होगी और यह इस स्तर पर एक दिन की जमा राशियों पर लागू होगी। हालांकि, यह उचित मूल्य निर्धारण के साथ, जब भी आवश्यकता होती है, लंबी अवधि की चलनिधि को अवशोषित करने के लिए लचीलापन बनाए रखेगा। एमएसएफ दर नीतिगत रिपो दर से 25 बीपीएस ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार, एलएएफ कॉरिडोर का विस्तार 50 बीपीएस के पूर्व-महामारी विन्यास में वापस आ गया, सममित रूप से नीतिगत

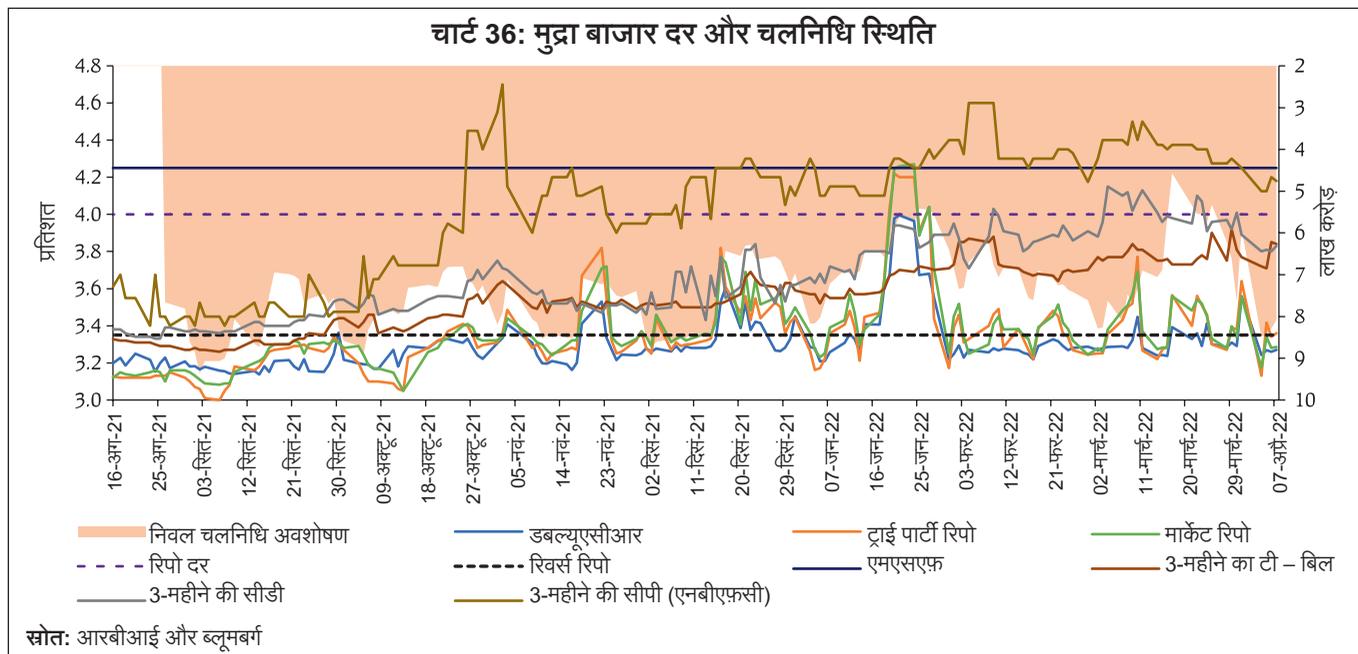
रिपो दर के आसपास, जो कॉरिडोर के केंद्र में होगा।

- निर्धारित दर रिवर्स रिपो (एफआरआरआर) दर को 3.35 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। यह रिज़र्व बैंक के साधनकिट के रूप में रहेगा और इसका परिचालन समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए रिज़र्व बैंक के विवेक पर होगा। एसडीएफ के साथ एफआरआरआर रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन को लचीलापन प्रदान करेगा।
- एमएसएफ और एसडीएफ दोनों साल भर सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेंगे।
- यह भी निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के लिए खुलने का समय 18 अप्रैल, 2022 से पूर्व-महामारी समय 9:00 बजे को बहाल कर दिया जाए, जो वर्तमान में इसके चल रहे समापन समय में कोई बदलाव किए बिना है।

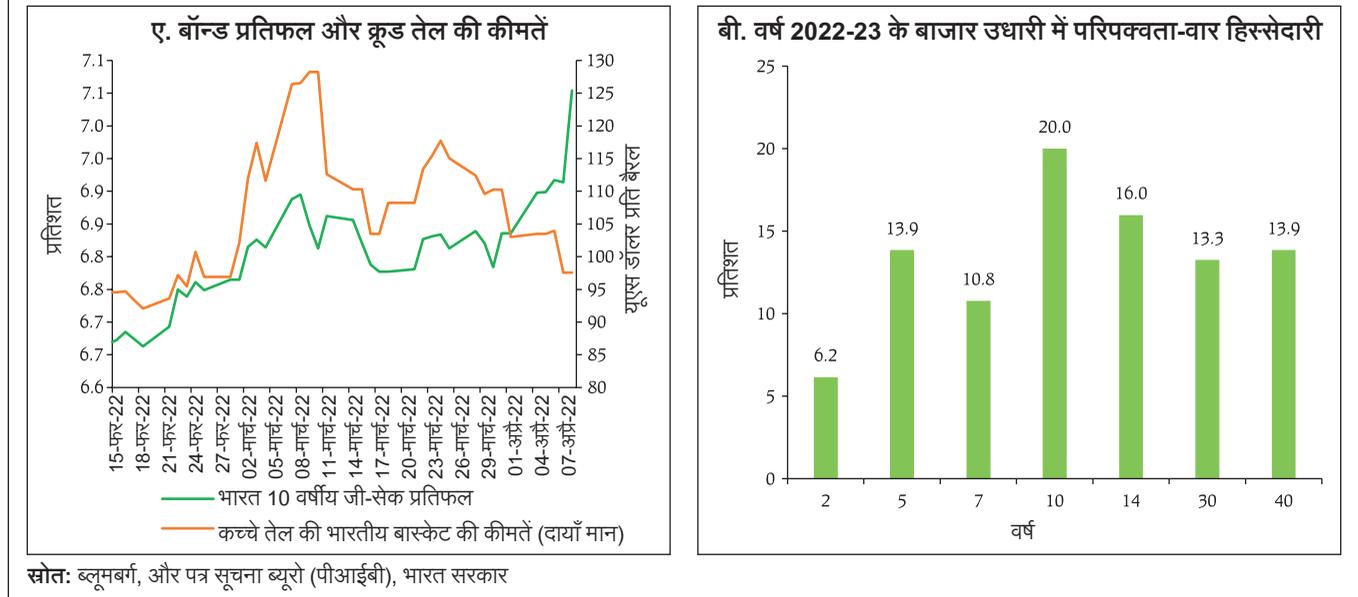
रिज़र्व बैंक ने यह भी संकेत दिया कि वह इस वर्ष की शुरुआत में गैर-विघटनकारी तरीके से एक बहु-वर्ष की समय सीमा में चलनिधि की क्रमिक और अंशांकित निकासी में संलग्न होगा। इसका उद्देश्य प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के आकार को मौद्रिक

नीति के रुख के अनुरूप स्तर पर बहाल करना है। रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की लाभदायक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। रिज़र्व बैंक सरकार के उधार कार्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आवश्यकतानुसार विभिन्न लिखतों को तैनात करता है।

मार्च 2022 के दूसरे पखवाड़े से 8 अप्रैल तक के दौरान, चलनिधि अवशोषण फरवरी के दूसरे पखवाड़े के दौरान से मार्च 2022 के मध्य तक अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण ₹8.4 लाख करोड़ से घटकर ₹7.3 लाख करोड़ हो गया। एफआरआरआर विंडो के तहत औसत दैनिक अवशोषण ₹2.9 लाख करोड़ था, जबकि औसतन कुल अवशोषण का 61 प्रतिशत मार्च के मध्य से 7 अप्रैल के दौरान परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामी (मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग दोनों) के माध्यम से था। रातोंरात मुद्रा बाजार दरों में एक सीमाबद्ध तरीके से कारोबार होता है, जिसमें भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) कॉरिडोर की निचली सीमा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। 3 महीने के टी-बिल और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जैसे लंबी अवधि के मुद्रा बाजार के लिखतों पर ब्याज दरें, हालांकि, ज़्यादा रहीं, और नीतिगत रिपो दर की ओर झुकी रहीं (चार्ट 36)।



चार्ट 37: बॉन्ड प्रतिफल और बाजार उधारी

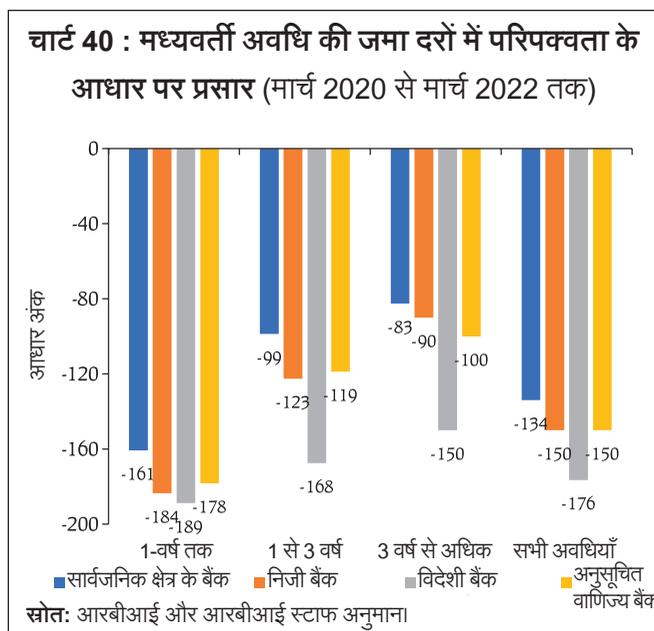
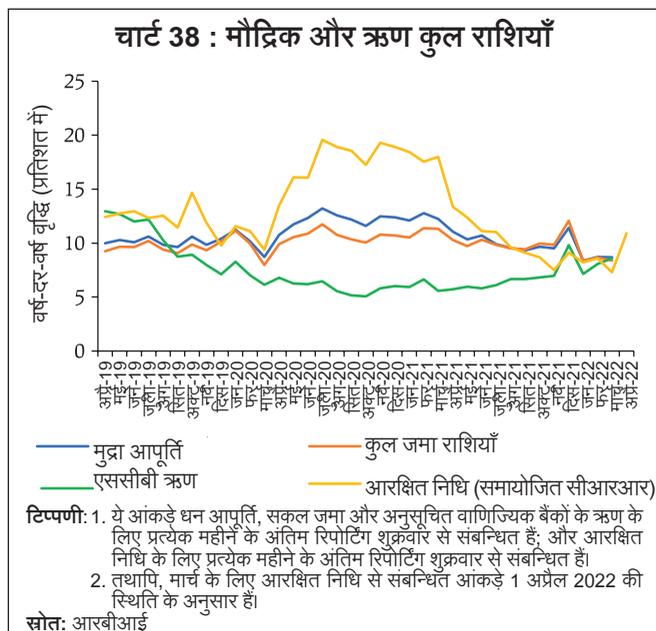


कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के साथ 16 मार्च से नरमी के बाद, 4 अप्रैल, 2022 को केंद्र सरकार के उधार कैलेंडर के जारी होने के बाद 10-वर्षीय मानदंड सुरक्षा पर प्रतिफल में वृद्धि हुई (चार्ट 37 ए)। इसके बाद, 10-वर्षीय मानदंड प्रतिफल (6.54% जीएस 2032)के साथ, 8 अप्रैल, 2022 को 7.12 प्रतिशत पर बंद होने के साथ, परिपक्वता स्पेक्ट्रम में बॉन्ड प्रतिफल सख्त हो गया। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि ने बाजार में गिरावट की धारणा कम कर दिया। बाजार उधार कैलेंडर सकल बाजार उधार के 59 प्रतिशत या 2022-23 पहली छमाही के लिए निर्धारित 8.5 लाख करोड़ के साथ सामने था। उधार को ₹32,000-33,000 करोड़ के 26 साप्ताहिक किशतों में पूरा किया जाना है, जिसमें से अधिकांश उधार 10-वर्षीय खंड में केंद्रित है (चार्ट 37बी)। 2022-23 के दौरान बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल, 2022 को हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्तमान सीमा को 31 मार्च, 2023 तक एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि बैंकों को इस बढ़ी हुई सीमा के तहत 1 अप्रैल, 2022 और 31 मार्च, 2023 के बीच अर्जित योग्य एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति दी जाए। एचटीएम की सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही से

चरणबद्ध तरीके से 23 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक फिर से लायी जाएगी।

मौद्रिक और ऋण की स्थिति मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप विकसित हुई। आरक्षित मुद्रा (आरएम) में, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2022 (एक साल पहले 14.5 प्रतिशत) की स्थिति के अनुसार 10.9 प्रतिशत की व-द-व वृद्धि हुई, प्रचलन में मुद्रा जो इसका प्रमुख घटक है उसमें 9.8 प्रतिशत (एक साल पहले 16.2 प्रतिशत) पर विस्तार हुआ। साथ ही, 25 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार मुद्रा आपूर्ति (एम3) 8.7 प्रतिशत (एक साल पहले 12.3 प्रतिशत) की दर से बढ़ी, जो मुख्य रूप से बैंकों के साथ कुल जमा में 8.4 प्रतिशत (एक साल पहले 11.3 प्रतिशत) की वृद्धि से प्रेरित थी। वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में वृद्धि, 25 मार्च, 2022 तक 8.6 प्रतिशत (एक साल पहले 5.6 प्रतिशत) तक बढ़ गई [चार्ट 38]।

बाह्य मानदंड प्रणाली की शुरुआत ने अतिरिक्त चलनिधि स्थितियों द्वारा प्राप्त सहायता के साथ उधार और जमा दरों के लिए मौद्रिक संचरण की सुविधा प्रदान की है। मार्च 2020 के बाद से नए और बकाया रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दरों

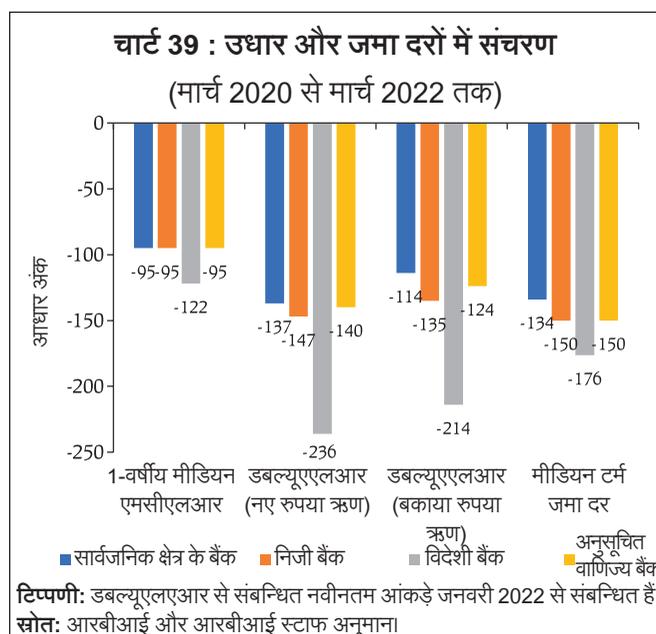


(डबल्यूएलआर) में क्रमशः 140 बीपीएस और 124 बीपीएस की गिरावट आई है। एससीबी की एक साल की औसत सीमांत लागत-आधारित दर (एमसीएलआर) में 95 बीपीएस की कमी आई है (चार्ट 39)।

इसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की औसत सावधि जमा दर (एमटीडीआर) में 150 आधार अंकों की गिरावट आई है (चार्ट 40)। प्रभाव-अंतरण एक वर्ष तक की छोटी अवधि

की जमाराशियों में अधिकतम है। बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों ने अपने समकक्षों की तुलना में सभी अवधियों में जमा दरों में बेहतर संचरण का प्रदर्शन किया है। ऋण मांग की बढ़ती प्रोफाइल के साथ, प्रमुख घरेलू बैंकों ने अपनी सावधि जमा दरों में वृद्धि की है।

भारत सरकार ने 2022-23 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत लिखतों (एसएसआई) पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ दिया। इस प्रकार, एसएसआई पर मौजूदा ब्याज दरें फॉर्मूला-आधारित दरों की तुलना में 9 से 118 बीपीएस अधिक हैं।



मार्च की दूसरी छमाही में वैश्विक इक्विटी बाजारों के साथ घरेलू इक्विटी में तेजी आई, 2018 के बाद से यूएस फेड द्वारा पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी को कम किया। रूस-यूक्रेन युद्ध पर चिंताओं के बावजूद, अप्रैल की शुरुआत में इक्विटी बाजारों में मार्च 2022 में जीएसटी संग्रह में प्रोत्साहन, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी की घोषणा के कारण तेजी आई। इसके बाद, 15-16 मार्च, 2022 की नवीनतम फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के मिनटों से नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बाजारों ने सुधार का प्रदर्शन किया, जिसने फेड के तुलन-

सारणी 3: इक्विटी प्रवाह

(US\$ million)

माह	चीन	भारत	इंडोनेशिया	कोरिया	मलेशिया	फिलीपींस	थाईलैंड	वियतनाम	ब्राजील	तुर्की	दक्षिण अफ्रीका
अप्रैल 21	11377	-1489	-244	68	-276	-285	-107	-33	1509	-274	526
मई 21	12038	749	247	-7964	-40	-253	-1061	-497	2372	198	55
जून 21	5485	1498	342	-792	-283	-87	-314	-191	2054	-66	-841
जुला 21	5253	-1706	67	-4222	-318	-183	-522	209	-1154	-98	-1156
अग 21	7837	1012	312	-5089	251	33	175	-277	-540	515	-1355
सितं 21	2910	1139	305	884	179	-47	338	-348	-1593	171	150
अक्टू 21	2332	-2271	926	-3228	378	8	474	-253	423	-155	-530
नवं 21	4357	-756	-214	3043	41	-3	-324	-397	217	1073	-363
दिसं 21	15821	-1741	101	2639	-270	1696	695	-129	-1430	-1136	-843
जन 22	1484	-4817	425	-3275	80	-56	432	-128	2160	-370	527
फर 22	654	-5018	1220	418	679	141	1931	-23	5804	-156	1501
मार्च 22	-6278	-3693	584	-3640	783	-204	1006	-156	5743	-779	1748
ति1: 2021-22	44901	1204	1029	-17115	-486	-823	-1491	-1136	2649	446	-2621
ति2: 2021-22	18370	-18297	3042	-4043	1690	1581	4214	-1085	12918	-1523	2041
2021-22	63271	-17093	4070	-21158	1203	759	2723	-2222	15566	-1077	-580

टिप्पणी: डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान; और एनएसडीएल

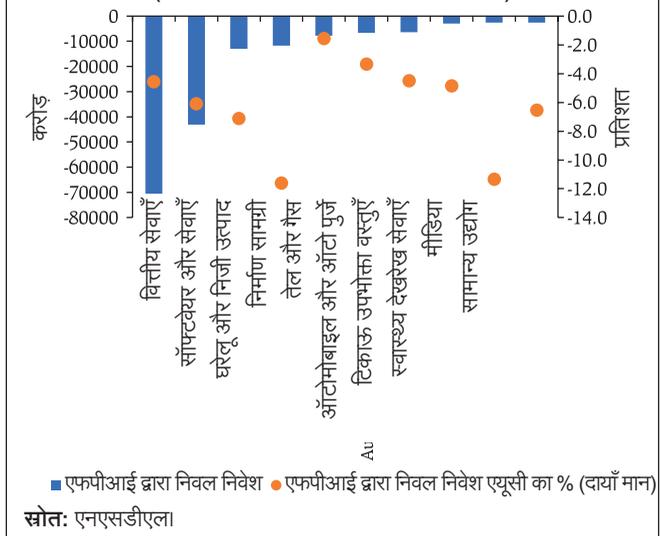
पत्र के आकार में कमी में वृद्धि का संकेत दिया। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दर में यथास्थिति की घोषणा और समायोजन में मौद्रिक नीति के रुख के रहने से बाजार में तेजी आई। हालांकि, वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने और चीन में कोविड -19 उछाल के बीच वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों के बाद बाजारों ने लाभ कम किया। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 12 अप्रैल, 2022 को फरवरी के अंत से 4.1 प्रतिशत बढ़कर 58,576 पर बंद हुआ है।

वित्तीय सेवाओं और सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र से बड़े बहिर्वाह के साथ, रूस-यूक्रेन युद्ध पर चिंताओं के बीच, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मार्च 2022 में लगातार छठे महीने घरेलू इक्विटी में निवल विक्रेता बन गए (सारणी 3 और चार्ट 41)।

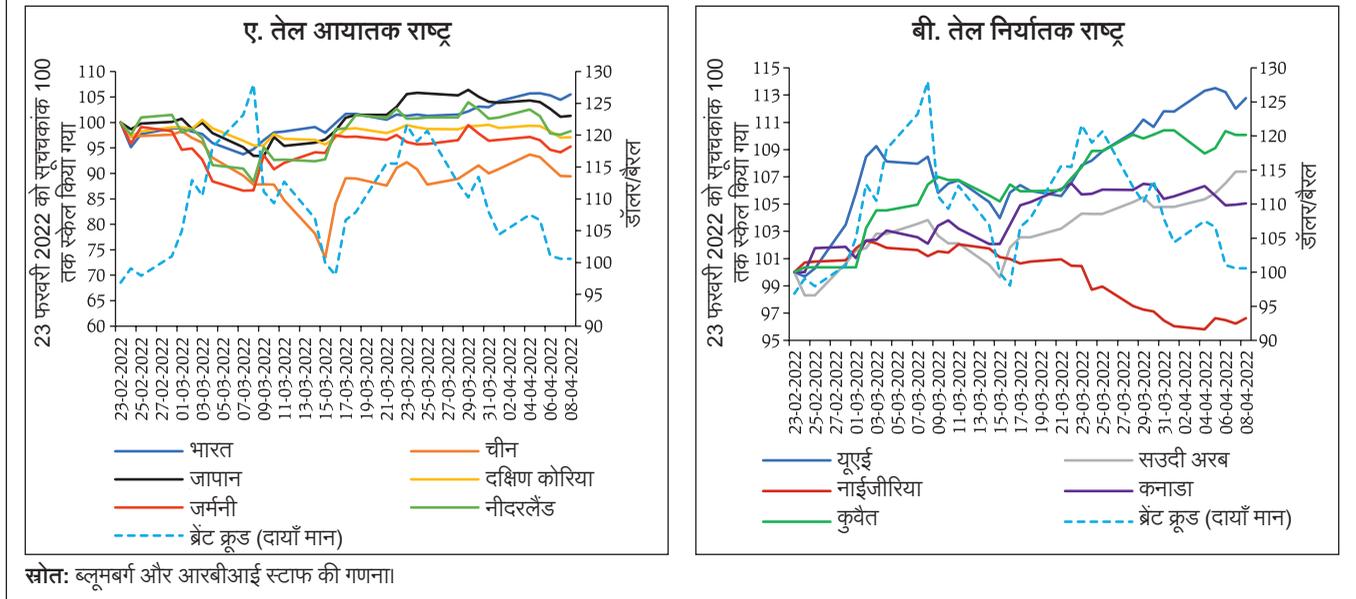
स्टॉक की कीमतों पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव में उल्लेखनीय अंतर तेल-आयातक और निर्यातक देशों के बीच देखा गया है (चार्ट 42)। भारत जो कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक है कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और तेल आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान, सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 76.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर एक साल पहले के अपने स्तर के बराबर रहा। विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं, संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, और खुदरा और थोक

चार्ट - 41 छ2 : 2021-22 में एफपीआई द्वारा निवल निवेश (10 सबसे बड़े बिकवाली वाले क्षेत्र)



चार्ट 42 एमएससीआई सूचकांकों में उतार-चढ़ाव



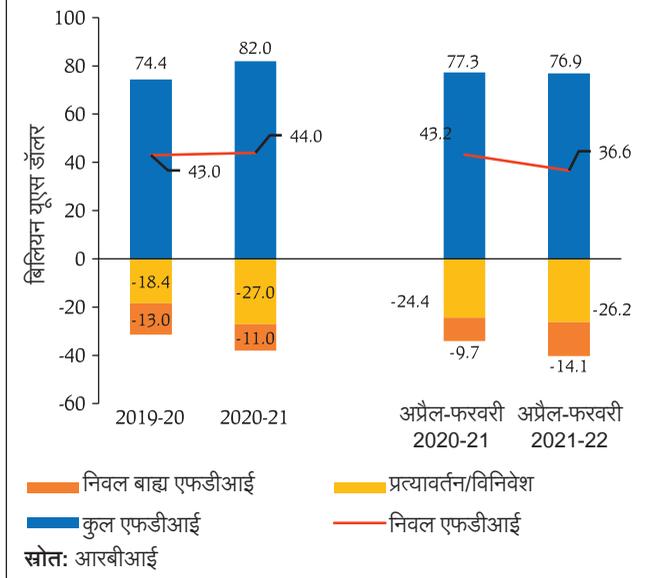
व्यापार क्षेत्र अधिकांश निवेश को आकर्षित करने में कामयाब रहे हालांकि, भारत से निवल विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण, निवल एफडीआई एक साल पहले के 43.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 36.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट 43)।

एफपीआई ने घरेलू बाजार से बाहर निकलना जारी रखा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का

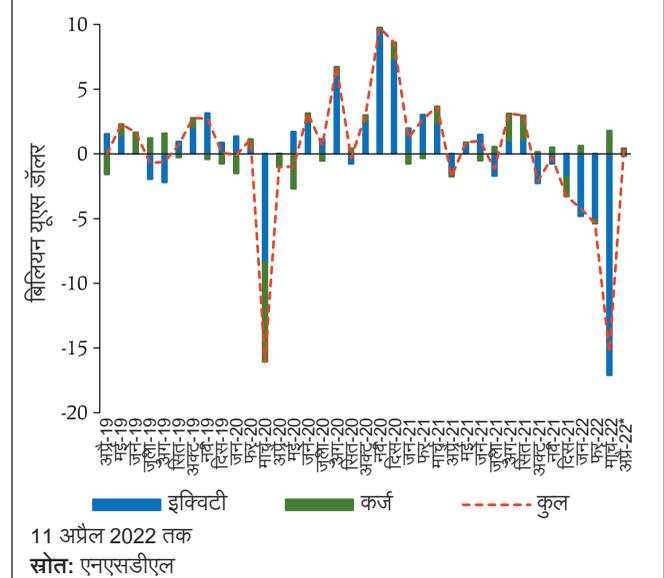
निवल बहिर्वाह हुआ। मार्च 2022 में, एफपीआई इक्विटी और कर्ज बाजार दोनों में शुद्ध विक्रेता थे (चार्ट 44)।

अंतर-कंपनी उधार सहित भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का निवल संवितरण अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान 11.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि एक साल पहले यह 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि निवल संवितरण चुकौती और अंतर-कंपनी उधार दोनों को छोड़कर एक साल

चार्ट 43 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



चार्ट 44: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश



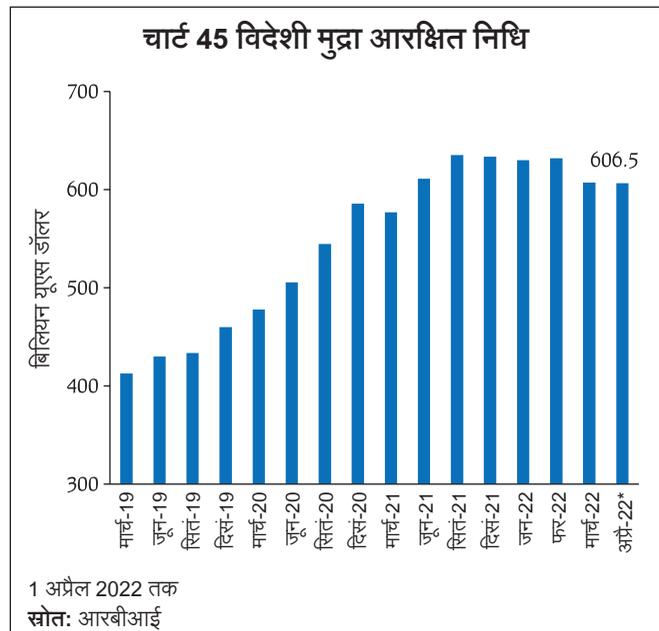
पहले के 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल पुनर्भुगतान की तुलना में 7.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। फरवरी में, रुपये के ऋणों के पुनर्वित्त, ऑन-लेंडिंग / सब-लेंडिंग और कार्यशील पूंजी के लिए काफी मात्रा में उधार लिया गया था।

1 अप्रैल, 2022 को विदेशी मुद्रा भंडार 606.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 के दौरान लगभग 12 महीनों के आयात के बराबर था (चार्ट 45)।

तेल आयात लागत बढ़ने और पोर्टफोलियो बहिर्वाह ने भारतीय रुपये (आईएनआर) पर दबाव बढ़ाना जारी रखा, जो मार्च 2022 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.6 प्रतिशत (म-द-म) तक गिर गया। नाममात्र और वास्तविक प्रभावी शर्तों (40-मुद्रा टोकरी) दोनों में, आईएनआर में एक महीने पहले के अपने स्तर से मार्च 2022 में 0.5 प्रतिशत तक मूल्यहास हुआ (चार्ट 46)।

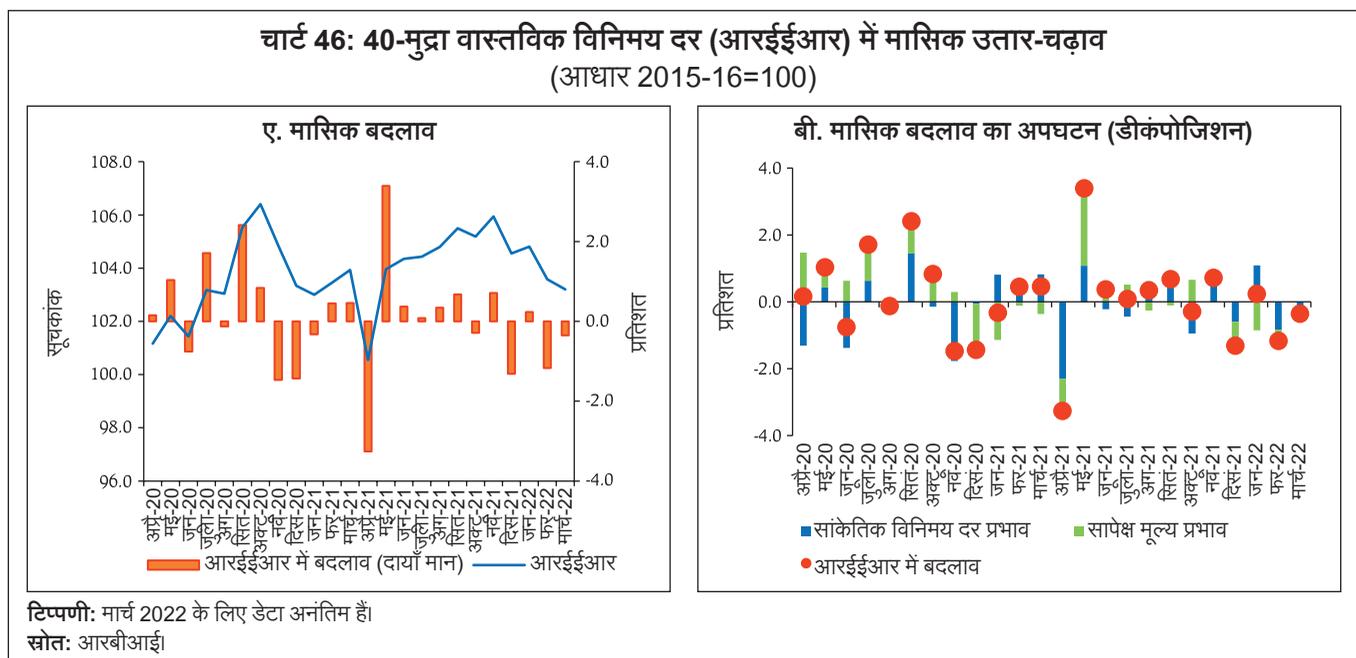
भुगतान प्रणाली

महामारी की तीन लहरों के माध्यम से, डिजिटल लेनदेन का प्रसार हुआ है। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पहल, फीचर फोन के लिए यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) (यूपीआई123पे), गैर-बैंकों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में शामिल करके भुगतान प्रणाली का व्यापक आधार, और प्रीपेड कार्ड की बकाया सीमा को



₹2 लाख तक बढ़ाना इस वृद्धि को और उत्प्रेरित करेगा (सारणी 4)।

बड़े मूल्य भुगतान खंड में, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से लेनदेन ने वर्ष के सभी महीनों में मजबूत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की। मार्च में खातों के वार्षिक समापन के साथ, आरटीजीएस लेनदेन ₹145 ट्रिलियन के 2.3



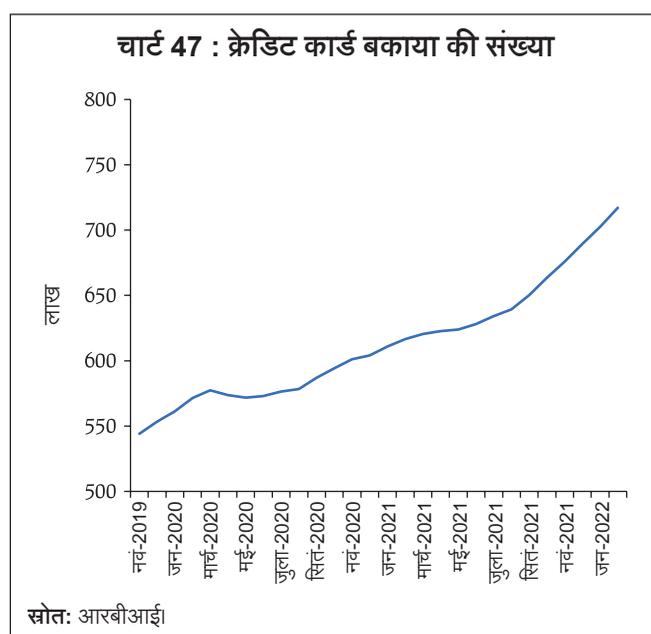
सारणी 4: चुनिंदा भुगतान प्रणाली में संवृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा वृद्धि प्रतिशत (व. द. व.)				लेनदेन मूल्य वृद्धि प्रतिशत (व. द. व.)			
	ति1:2021-22	ति2:2021-22	ति3:2021-22	ति4:2021-22	ति1:2021-22	ति2:2021-22	ति3:2021-22	ति4:2021-22
आरटीजीएस	62.5	36.9	24.9	14.5	23.6	27.3	25.6	12.9
एनईएफटी	40.1	35.1	25.2	26.1	27.0	12.8	7.2	14.2
यूपीआई	123.4	112.7	99.1	98.6	142.4	107.0	98.3	92.4
आईएमपीएस	85.8	49.4	26.8	31.5	70.9	34.7	34.2	38.5
एनएसीएच	-12.0	-3.0	13.4	20.2	3.6	13.5	11.0	13.3
एनइटीसी	197.7	100.0	73.9	48.6	157.7	71.8	56.1	40.8
बीबीपीएस	155.2	162.7	146.7	116.6	197.7	180.0	168.7	134.0

स्रोत: आरबीआई

करोड़ लेनदेन पर पहुंच गया। खुदरा क्षेत्र में, डिजिटल भुगतान ने 64 प्रतिशत की वार्षिक मात्रा वृद्धि (मूल्य के संदर्भ में 28 प्रतिशत की वृद्धि) दर्ज की। डिजिटल लेनदेन की मात्रा में यूपीआई का बोलबाला था। खुदरा क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शनकर्ता राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) थे। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कारण आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) में भी काफी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली के तहत जारी किए गए फास्टैग्स की संख्या में 2021-22 में 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे बकाया टैगों की कुल संख्या लगभग 4.8 करोड़ हो गई। 2021-22 में डिजिटल इकोसिस्टम की एक उल्लेखनीय विशेषता क्रेडिट कार्ड का पुनरुत्थान था, मार्च 2021 के बाद से औसत लेनदेन का आकार दोहरे अंकों की दर से बढ़ रहा है (चार्ट 47)।

समावेशी डिजिटल भुगतान के लिए लक्षित हस्तक्षेप कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर के भौगोलिक प्रसार का पता लगाना आवश्यक है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 25 मार्च 2022 को भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया⁸ इस फ्रेमवर्क के लिए बैंकों और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों को बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों और कागज़-आधारित / सॉफ्ट क्यूआर कोड से संबंधित जियो-टैगिंग जानकारी रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता



है। यूपीआई के उपयोग के माध्यम से ग्राहक को अधिकृत करने का कार्य जारी है, जो सभी बैंकों और सभी एटीएम नेटवर्क/ऑपरेटरों में कार्ड-रहित नकद निकासी सुविधा को प्रोत्साहित करेगा।

V. निष्कर्ष

निकट-अवधि का वैश्विक दृष्टिकोण गंभीर प्रतीत होता है, भू-राजनीतिक जोखिमों के भंवर में फंस गया है, जो तेजी से भौतिकता की ओर जा रहा है, आपूर्ति श्रृंखलाओं में तनाव और मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की गति तेज हो रही है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं जोखिम भावनाओं में तेजी से बदलाव और वैश्विक वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही हैं जो

⁸ <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12260&Mode=0>

वास्तविक अर्थव्यवस्था के परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं जो प्रारंभिक रिकवरी को विफल कर सकती हैं या यहां तक कि तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी को दूर कर सकती हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था इन नकारात्मक बाह्यताओं से अछूती नहीं है। कमोडिटी की कीमतों में उछाल खासकर बढ़ते आयात के माध्यम से पहले से ही मुद्रास्फीति जोखिम पैदा कर रहा है। पोर्टफोलियो पूंजी बहिर्वाह के साथ सह-अस्तित्व में तेजी से बढ़ते व्यापार और चालू खाता घाटे का बाहरी धारणीयता पर भार होता

है, हालांकि अंतर्निहित सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय भंडार का स्टॉक बफर प्रदान करता है।

भारत इन चुनौतियों का सामना व्यापक वैक्सीन कवरेज, वित्तीय क्षेत्र की आघात सहनीयता, मजबूत निर्यात और विप्रेषण और राजकोषीय पुनर्मूल्यांकन से फ्रेमवर्क पर पूंजीगत व्यय को बढ़ाने से प्राप्त मजबूत स्थिति से करता है। आगे बढ़ते हुए, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।

अनुबंध

उत्पादकता पर रोबोटिक्स का प्रभाव और जीडीपी में श्रम की हिस्सेदारी

महामारी ने बड़े पैमाने पर श्रमिकों की अनुपलब्धता और प्रतिबंधित भौतिक निकटता के साथ दुनिया भर में रोबोट अपनाने⁹ की दर को बढ़ा दिया है (सेदिक एवं अन्य, 2021)। हालांकि, जॉर्जिया एवं अन्य, ओईसीडी देशों में स्वचालन के कारण 14 प्रतिशत निम्न-स्तरीय नौकरियों के जोखिम की भविष्यवाणी करता है। दूसरी ओर, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने 2015-2065 की अवधि के लिए स्वचालन से उत्पादकता में 0.8-1.4 प्रतिशत की वृद्धि की भविष्यवाणी की है। इसने उत्पादकता और रोजगार पर स्वचालन के प्रभाव पर बहस फिर से शुरू कर दी है। रोबोटिक्स उद्योग का कुल बाजार आकार 2020 में 55.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2028 तक बढ़कर 165.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है (स्टेटिस्टा)। अपनी 52 प्रतिशत स्वचालन क्षमता (मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट) के साथ, भारत पर रोबोटिक्स का प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि और निचले स्तर के श्रमिकों के विस्थापन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार, भारत ने 2008-2020 की अवधि के लिए दुनिया भर में दर्ज किए गए 15 प्रतिशत के मुकाबले रोबोट की नई स्थापनाओं की औसत वार्षिक वृद्धि दर 20 प्रतिशत देखी है।

उत्पादकता और रोजगार पर रोबोटिक्स के प्रभाव पर साहित्यिक विचार को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि अधियन एवं अन्य द्वारा चित्रित किया गया है, पहला दृश्य, यानी, विस्थापन प्रभाव रोजगार और श्रम हिस्सेदारी पर स्वचालन के नकारात्मक प्रभाव पर केंद्रित है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण (उत्पादकता प्रभाव) फर्म स्तर पर रोजगार पर स्वचालन के सकारात्मक प्रभाव के अस्तित्व को मानता है। हालांकि, विस्थापन और उत्पादकता प्रभाव दोनों के अस्तित्व पर सर्वसम्मति उभरती हुई प्रतीत होती है।

उत्पादकता और विस्थापन प्रभावों के प्रभुत्व के संबंध में परिकल्पना की जांच करने के लिए, 2008 से 2018 की अवधि के लिए निश्चित प्रभाव पैनेल अनुमान का उपयोग करके 14 देशों के नमूने का विश्लेषण किया गया है। मॉडल नई स्थापनाओं के साथ फू एवं अन्य (2021) पर आधारित है, प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रोबोटों को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया। सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात और आयात हिस्सेदारी के नियंत्रण चर को व्यापार के खुलेपन के लिए शामिल किया गया है जबकि जनसंख्या और पूंजीगत स्टॉक को वृद्धि के पारंपरिक मापदंडों के रूप में शामिल किया गया है। माध्यमिक विद्यालय नामांकन दर और भरे गए पेटेंट की संख्या को शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए प्रॉक्सि के रूप में लिया जाता है। परिणाम बताता है कि स्थापित नए रोबोटों में 1 प्रतिशत की

वृद्धि से श्रम उत्पादकता में 0.031 प्रतिशत की वृद्धि होती है। जबकि श्रम मुआवजे के हिस्से पर स्वचालन का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।

परिणाम सकल घरेलू उत्पाद में श्रम मुआवजे के हिस्से पर मानव पूंजी के नकारात्मक प्रभाव को भी उजागर करते हैं जब रोबोटिक्स के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियंत्रण चर के रूप में लिया जाता है। यह रोबोटिक्स की शुरुआत से लिए गए पूर्ण उत्पादकता लाभ का इष्टतम उपयोग करने के लिए, कार्यबल को शिक्षित करने और फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह मानव पूंजी के प्रभाव में परिवर्तन, पेटेंट और स्थापित नए रोबोटों की संख्या, सकल घरेलू उत्पाद में श्रम मुआवजे के हिस्से पर, जब मानव पूंजी में तीन अवधि के अंतराल को एक स्वतंत्र चर के रूप में लिया जाता है, से प्रमाणित होता है। ये परिणाम बर्ग एवं अन्य (2016) के अनुरूप प्रतीत होते हैं, जो श्रम उत्पादकता में वृद्धि और कुल आय में पूंजी के एक उच्च हिस्से का सुझाव देता है। कुल मिलाकर, परिणाम बताते हैं कि 2008-2018 के दौरान विश्लेषण किए गए देशों के नमूने के लिए उत्पादकता प्रभाव विस्थापन प्रभाव पर हावी है, जिससे फू एवं अन्य

श्रम उत्पादकता और सकल घरेलू उत्पाद में श्रम की हिस्सेदारी पर रोबोटिक्स के अनुमानित प्रभाव

	(1)	(2ए)	(2बी)
	निर्भर चर		
	उत्पादन प्रति श्रमिक	सकल घरेलू उत्पाद में श्रम मुआवजे का हिस्सा	सकल घरेलू उत्पाद में श्रम मुआवजे का हिस्सा
नए लगाए गए रोबोट का अभिलेख	0.0316**	-0.00583	0.0000287
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निर्यात का हिस्सा	-0.00169	-0.0120***	-0.0177**
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आयात का हिस्सा		0.00951**	0.0154**
मानव पूंजी	0.00351**	-0.00126*	
मानव व्यक्ति (पिछड़ा)			0.00300
कुल जनसंख्या का अभिलेख	0.00475*		
स्टॉक पूंजी		0.0755***	0.0792**
निवासियों द्वारा भरे गए पेटेंटों की संख्या का अभिलेख		-0.0253	0.0233
स्थिर	10.26***	1.091**	0.0876
पर्यवेक्षण	127	126	90
आर-वर्गित	0.748	0.209	0.194

टिप्पणी: ***, **, * महत्व के स्तर को क्रमशः 1%, 5% और 10% पर दर्शाते हैं।

(जारी)

⁹ प्रति 1000 कर्मचारियों पर नए रोबोट इंस्टॉलेशन द्वारा मापा जाता है।

(2021) द्वारा प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों की पुष्टि होती है। इसके अलावा, निम्न-मध्यम कौशल श्रमिकों के मौजूदा कौशल को पुनः व्यवस्थित करके विस्थापन के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

संदर्भ:

Aghion P, Antonin C, Bunel S, Jaravel X. The Direct and Indirect Effects of Automation on Employment: A Survey of the Recent Literature (forthcoming).

Fu, X., Bao, Q., Xie, H., Fu, X. (2021). Diffusion of Industrial Robotics and Inclusive Growth: Labour Market Evidence from Cross Country Data. *Journal of Business Science*.

Georgieff, A., Milanez, A. (2021). What happens to jobs at high risk of automation? OECD Social, Employment and Migration Working Papers.

Sedik, T.S., Yoo, J. (2021). Pandemics and Automation: Will the Lost Jobs Come Back? IMF Working Paper.